● वर्ष-3
● अंक-270
रायपुर, शुक्रवार
21 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

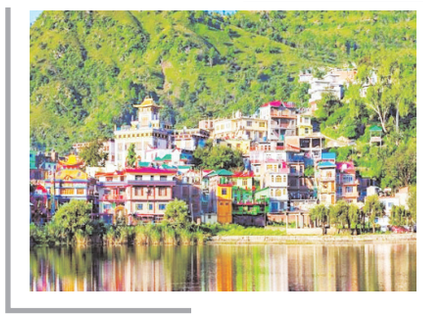

पेज-6›› 'हिल्स की वाराणसी' में हैं 81 मंदिर....

कांकेर के चार बूथों की ईवीएम की जांच होगी

रायपुर। कांकेर लोकसभा के 3 विधानसभा के 4 बूथों पर ईवीएम की जांच होगी. इसमें बालोद में 2, गुंडरदेही में 1, सिहावा में 1 केंद्र में ईवीएम की जांच होगी. इसके आदेश चुनाव आयोग ने दिए है. इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बिरेश ठाकुर ने की थी. चुनाव आयोग ने बिरेश ठाकुर के आवेदन को मंजूर करते हुए ईवीएम के जांच के आदेश दिए हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की थी. शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका को मंजूर करते हुए जांच के आदेश दिए हैं. बता दें कि बिरेश ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि मतदान के बाद, जो ईवीएम के नंबर एजेंट को दिए गए थे. मतगणना के दिन वो नंबर बदल कैसे गए.

इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना होगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस ईवीएम पर

गड़बड़ी को आशंका हो उसकी जांच करवाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने 4 ईवीएम जहां ईवीएम नंबर अलग-अलग है उनके जांच के लिए आवेदन किया है. बीरेश ठाकुर ने तत्कालीन कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 16वें राउंड के बाद 2 घंटे तक मतगणना का कोई अपडेट ही नहीं दिया गया. बीरेश ठाकुर ने कांकेर कलेक्टर के मोबाइल डिटेल जांच करने की भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से फोन आने लगे थे. अगर उनके काल डिटेल की जांच की जाए तो सब साबित हो जाएगा. इसके साथ ही बीरेश ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका रही है और इसलिए तत्कालीन कलेक्टर को आचार संहिता हटते ही प्रमोशन कर गृह और जेल विभाग का सचिव बनाया गया है.

1884 वोटों से हारे बिरेश ठाकुर- बता दें कि कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया था और कांग्रेस ने बिरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था. चुनाव में भोजराज नाग को 5 लाख 97 हजार 624 वोट मिले और बिरेश ठाकुर 5 लाख 95 हजार 740 वोट मिले. चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग 1884 वोटों से जीतकर सांसद बने हैं.

निर्वाचन आयोग को छह राज्यों की आठ लोकसभा सीट पर ईवीएम सत्यापन के आवेदन मिले

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग को चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लगी माइक्रो-कंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ या हेरफेर संबंधी सत्यापन के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों से आठ आवेदन मिले हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ के संदेह को ''निराधार'' करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के भीतर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है और ऐसी स्थिति में माइक्रो-कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अदालत ने कहा था कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। अहमदनगर (महाराष्ट्र) से भाजपा के उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों से संबंधित ईवीएम का सत्यापन कराने की मांग की है।

भाजपा सांसद भर्तृहरि होंगे अगले प्रोटेम स्पीकर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी है। ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा सत्र के मद्देनजर इस पद पर नियुक्त किया गया है। बता दें कि महताब सात बार के सांसद हैं और अगले स्थायी स्पीकर की नियुक्ति तक वे सदन में स्पीकर की सभी जिम्मेदारियां निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भाजपा सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू का कहना है कि लोकसभा सदस्य के. सुरेश, टीआर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय प्रोटेम स्पीकर महताब की सहायता करेंगे। उन्होंने आग बताया कि भर्तृहरि महताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे।

कौन हैं भर्तृहरि महताब?- भर्तृहरि महताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस वर्ष लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल (बीजद) को बड़ा झटका देते हुए पार्टी की स्थाई सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही वे भाजपा में शामिल हो गए थे।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों होती है?- प्रोटेम स्पीकर को संसद के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति तब की जाती है, जब नियमित स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम निर्वाचित किए गए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसके अलावा नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना होता है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अस्थाई होती है और नए स्पीकर के चयन के बाद यह जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है।

छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्धः प्रधान

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बीच केंद्र ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ब्रीफिंग में कहा, हम शून्य-त्रुटि परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और एनटीए कामकाज में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा के संदर्भ में हम बिहार सरकार के संपर्क में हैं। हमें पटना से कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। पुलिस पुलिस जांच कर रही है और उनके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। विश्वसनीय जानकारी के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार

जांच के लिए बनाएंगे हाई लेवल कमेटी

एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने जा रही है। उस उच्च स्तरीय समिति से एनटीए, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए सिफारिशों की अपेक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर एनटीए के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधान ने कहा कि एक अलग घटना (बिहार पेपर लीक) का असर उन लाखों छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था को सुधारना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि डार्क नेट पर यूजीसी-नेट प्रश्नपत्र यूजीसी-नेट के मूल प्रश्नपत्र से मेल खाता है, हमने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया।

शिक्षामंत्री ने कहा कि मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमें उन लाखों मेधावी छात्रों के हितों पर ध्यान देना होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके वह परीक्षा उत्तीर्ण की है।

जनता को हमारी नीयत और नीतियों पर भरोसाः मोदी

जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (20 जून) जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में एम्पावरिंग यूथ, ट्रांसफॉर्मिंग जेएंडके कार्यक्रम में शामिल हुए। वह 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी ने नए रंगरूटों को सरकारी सेवा नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं और यह किसी देश के लिए

बहुत बड़ी शक्ति है। जब आकांक्षाएं ऊंची होती हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी ऊंची होती हैं। ऐसे मापदंडों पर हमारा मूल्यांकन करने के बाद जनता ने हमें तीसरी बार चुना। एक आकांक्षी समाज दूसरा मौका नहीं देता। इसका एकमात्र पैरामीटर प्रदर्शन है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज हम जम्मू-कश्मीर में जो बदलाव देख रहे हैं, वह पिछले 10 साल के हमारे काम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ हम पर विश्वास और इस विश्वास व उनकी आकांक्षा को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत और नीतियों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर चलते हुए हमारी सरकार प्रदर्शन करके दिखाती है, रिजल्ट लाकर दिखाती है। इसी प्रदर्शन के आधार पर 60 साल के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश में जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्थिरता का है।

भाजपा करेगी प्रदेश भर में योग शिविर का आयोजन

रायपुर। भाजपा अंतरराष्ट्रीय योग कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर, उपमुख्यमंत्री अरूण साव कोरबा तथा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर में, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े साइंस कॉलेज रायपुर में, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर में, बिलासपुर में केन्द्रीय संघ राज्य मंत्री तोखन साहू, कांकेर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कोरिया में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुद में मंत्री दयालदास बघेल, कबीरधाम में मंत्री लखनलाल देवांगन, बलौदाबाजार में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, धमतरी में मंत्री टंकराम वर्मा, राजनांदगांव में सांसद संतोष पाण्डेय, सरगुजा में सांसद चिन्तामणी महाराज, जशपुर में सांसद राधेश्याम राठिया, सुकमा में सांसद महेश कश्यप, गरियाबंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चैधरी, सहित पूरे मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में योग दिवस के दिन योग कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रमुख समाचार

केजरीवाल को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से जांच एजेंसी को जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। हालांकि, विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील कल संबंधित जज के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय घटनाक्रम में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। मई में आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था॥

कर्नाटक में रह रहे लोगों को कन्नड़ सीखना चाहिए

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपनी मातृबोलने में गर्व महसूस करने का अनुरोध करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा, भूमि और जल को बचाना हर कन्नडिगा का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रह रहे लोगों को कन्नड़ सिखना चाहिए। उन्होंने राज्य में 'कन्नड़ माहौल' बनाने की जरूरत पर बल दिया। यहां विधान सौध के परिसर में नदा देवी भुवनेश्वरी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा के निर्माण के वास्ते 'भूमि पूजा' करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मातृबोलना गर्व का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा, '' एक संकल्प लिया जाए कि राज्य में कन्नड़ के सिवा कोई नहीं बोली जाए। कन्नडिगा उदार होते हैं। यही कारण है कि कर्नाटक में ऐसा माहौल है कि जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, वे भी कन्नड़ सीखे बिना रह सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ सकती है। वे बस अपनी मातृमें ही बोलते हैं।'' कन्नडिगाओं से अपनी मातृमें बोलने का अनुरोध करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि इसे लेकर हीनता का बोध नहीं पालने की जरूरत है।

आरक्षण मामलाः सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आरक्षण में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी को रद्द करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम आहत हैं और हमें पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि बीजेपी आरक्षण को रोकने की कोशिश करेगी। हमने चुनाव के दौरान पहले ही कहा था कि बीजेपी वाले आरक्षण के खिलाफ हैं। तेजस्वी ने कहा कि आपको पता ही होगा कि जब हमने जाति आधारित सर्वे कराया तो बीजेपी के लोगों ने इसे रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की, लेकिन अंत में हमारी जीत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीएम इस पर चुप क्यों हैं? मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार द्वारा लाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच पर आदेश पारित किया। हालांकि, अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी›

भारत में इस गर्मी में दर्ज की गईं 114 मौतें

नई दिल्ली। भारत में 1 मार्च से 18 जून के बीच कम से कम 114 मौतें और संदिग्ध हीटस्ट्रोक के 40,984 से अधिक मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। देश भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 37 मौतों के साथ सबसे अधिक मौतें हुईं, इसके बाद बिहार, राजस्थान और ओडिशा का स्थान है। एक अधिकारी ने कहा कि वास्तविक आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं क्योंकि सभी राज्यों ने अपना अंतिम डेटा जमा नहीं किया है। संकट के जवाब में, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के अस्पतालों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने हीटवेव से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। 19 जून को उत्तरी और पूर्वी भारत में लू के कारण चार लोगों की मौत हो गई। केंद्र ने अस्पतालों को हीटस्ट्रोक रोगियों की देखभाल के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने की सलाह दी।

77 फीसदी भारतीय चाहते हैं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत उपाय

नई दिल्ली। भारत के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को एक सर्वेक्षण जारी किया गया। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 77 फीसदी भारतीय चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कदम उठाए जाएं। वहीं, 33 फीसदी लोगों ने हाल ही में चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव किया है। दरअसल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जियोपोल के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने पीपुल्स क्लाइमेट वोट-2024% सर्वेक्षण आयोजित किया। इस सर्वेक्षण में 77 देशों के 75 हजार से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं। इन लोगों ने दुनिया की आबादी का 87 फीसदी का प्रतिनिधित्व किया। सर्वेक्षण से दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों में जलवायु उपायों के लिए मजबूत समर्थन का पता चलता है। अमेरिका और रूस में 66 फीसदी, जर्मनी में 67 फीसदी, चीन में 73 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका और भारत में 77 फीसदी, ब्राजील में 85 फीदी, ईरान में 88 फीसदी और इटली में 93 फीसदी लोगों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उपायों की मांग की। वहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए अधिक समर्थन दिखाया। सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन की चिंता व्यापक स्तर पर है।

राजनीति पहले जैसी शालीन नहीं हो सकती

बलबीर पुंज

लोकसभा-विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में एक महत्वपूर्ण घटना की जाने-अनजाने में अनदेखी जैसी हो गई। ओडिशा में 24 वर्ष बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां भाजपा पहली बार बीजू जनता दल (बीजेडी) को परास्त करके अपने बल पर सरकार बनाने में सफल हुई है। जब 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब न केवल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी दल बीजेडी के मुखिया नवीन पटनायक शामिल हुए, बल्कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें मंच पर भी स्थान दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के शीर्ष नेता पटनायक से सहज होकर मिले। आखिर भारतीय राजनीति में राजनीतिक-वैचारिक विरोधी को प्रतिद्वंद्वी के बजाय शत्रु मानने की विकृति कहां से आई?

स्वतंत्रता से पहले भी विभिन्न राजनीतिज्ञों में मतभिन्नता थी। परंतु वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे। एक ही ध्वज के तले संवाद होता था। कुछ पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी मिलकर काम कर चुके थे। तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 'भारत-रत्न' पंडित मदन मोहन मालवीय ने न केवल वर्ष 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की, बल्कि कांग्रेस में सक्रिय रहते हुए हिंदू महासभा के पांच विशेष सत्रों की अध्यक्षता भी की। इसी तरह गांधीजी वीर सावरकर को 'भाई' कहकर संबोधित करते थे, तो वह संघ के अनुशासन से प्रभावित थे। आचार-विचार में मतभेद होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई, 1944 में गांधीजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें पहली बार 'राष्ट्रपिता' की संज्ञा दी थी। भारतीय जनसंघ (अब भाजपा) के सह-संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और संविधान-निर्माता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, दोनों कांग्रेस विरोधी थे। स्वतंत्रता से पहले डॉ. श्यामाप्रसाद हिंदू महासभा, तो डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति संघ के नेता थे। परंतु गांधीजी की सलाह पर इन दोनों गैर-कांग्रेसी नेताओं के साथ पैंथिक पार्टी के बलदेव सिंह, जस्टिस पार्टी के आर. के. षण्मुखम चेट्टी को भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। संभवतः यह स्वतंत्र भारत की पहली गठबंधन सरकार थी।

स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक वर्षों में भी राजनीतिक शालीनता और शुचिता तुलनात्मक रूप से ऐसी ही थी। यह प्रतिरोधी विचारधाराओं के ध्वजवाहक पं. नेहरू द्वारा अटलजी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी और वाजपेयी द्वारा नेहरू के निधन पर व्यक्त भावुक श्रद्धांजलि देने तक में स्पष्ट है। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में संघ की निस्वार्थ राष्ट्रसेवा देखने और पूर्वाग्रह के बादल छंटने के बाद 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में पं. नेहरू द्वारा आरएसएस को आमंत्रित करने, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के आमंत्रण पर संघ के तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के सामरिक बैठक में पहुंचने, मई, 1970 और मई, 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वीर सावरकर के सम्मान में डाक-टिकट जारी करते हुए उन्हें राष्ट्र-जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति बताने और संघ की शाखाओं में प्रातः स्मरण में गांधीजी को स्थान देने आदि से भी यह वातावरण परिलक्षित होता है।

भारत में राजनीतिक-वैचारिक विरोधियों को दुश्मन जैसा मानने का चलन वामपंथ की प्रणाली से प्रारंभ हुआ। हिंसा और असहमति रखने वालों के प्रति असहिष्णु होना-इसके केंद्र में है। दशकों से वामपंथ के गिरफ्त रहा प. बंगाल और केरल राजनीतिक रक्तपात, दूसरे विचार के प्रति असहिष्णुता और विरोधियों की हत्याओं के मामले में सर्वाधिक दागदार है। अविभाजित भारत में वामपंथ की राजनीतिक इकाई का उदय 26 दिसंबर, 1925 में हुआ था। भले ही इस असहिष्णु दर्शन ने कालांतर में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में ब्रितानियों के लिए मुखबिरी की, गांधीजी-नेताजी के लिए अपशब्द कहे, पाकिस्तान के जन्म में दाई की भूमिका निभाई, भारतीय स्वतंत्रता को अस्वीकार किया, भारत को 17 देशों का समूह बताया , 1948 में भारतीय सेना के खिलाफ हैदराबाद के जिहादी रजाकरों को पूरी मदद दी, 1962 की लड़ाई में चीन का समर्थन किया, इसके बावजूद वामपंथ से देश की मुख्यधारा की राजनीतिक शुचिता अप्रभावित रही। लेकिन जब 1969-71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए वामपंथियों का समर्थन लिया, तो यह राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बन गया। इससे कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र तक बदला। कांग्रेस द्वारा देश पर आपातकाल थोपकर हजारों विरोधियों को जेल में ठूंसना-इस घालमेल का प्रारंभिक लक्षण था। यह स्वभाव वर्ष 2004 में मणिशंकर अय्यर द्वारा बतौर मंत्री अंडमान-निकोबार की जेल से सावरकर के विचारों को हटाने से लेकर अब तक स्वघोषित सेक्यूलरवादियों द्वारा भाजपा-संघ-मोदी के नाम पर अक्सर गरियाने और मुखर घृणा भाव दिखाने आदि की शक्ल में जारी है। दलों और नेताओं के बीच सहज सौहार्द और शालीनता के उदाहरण बिरले हो चले हैं।

अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस ने थाने का किया घेराव

■ चोरी की जब्त रेत गायब होने पर उठाया सवाल

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस आक्रामक हो गई है। इसी कड़ी में, आज कांग्रेस ने सरकारी रेत चोरी के मामले को लेकर डोंगरगढ़ थाने का घेराव कर दिया। मामला डोंगरगढ़ के ग्राम मुड़पार का है, जहाँ बीते दिनों सड़क के किनारे भारी मात्रा में रेत का डंप मिला था। डोंगरगढ़ एसडीएम ने इस रेत को जब्त किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस डंप रेत को लेकर आज मोर्चा खोल दिया और बड़ी रेत चोरी का आरोप लगाते हुए दोषियों पर एफआईआर की मांग की।

यह घटना 30 मई 2024 की है जब एसडीएम और नायब तहसीलदार अपने कर्मचारियों के साथ ग्राम मुड़पार पहुँचे और बड़ी मात्रा में रेत को जब्त किया। आज, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजयराज सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुँचे और ज्ञापन सौंपा।

विजयराज सिंह ने बताया कि यह कोई छोटी-मोटी चोरी नहीं है, बल्कि 800 ट्रिप रेत की चोरी का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम मुड़पार से जामरी तक 800 ट्रिप रेत निकाली गई और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। जब प्रशासन को पता चला, तो जब्ती की कार्यवाही की गई, लेकिन जब्त की गई रेत का अता-पता नहीं है।

सिंह ने यह भी आरोप लगाया, कि राजनादगांव निवासी प्रतीक अग्रवाल और बेलगांव निवासी लेखराम साहू को रेत डंप हटाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन रेत को हटाकर क्या किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस को जानकारी मिली कि उक्त रेत को बेंच दिया गया है, जबकि जब्ती से प्राप्त संपत्ति शासकीय मानी जाती है। शासकीय संपत्ति को बिना कागजी कार्यवाही और खनिज विभाग को सूचना दिए बगैर बेचना एक बड़ी चोरी है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 800 ट्रिपर रेत की चोरी करोड़ों का मामला है, जिसमें शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका है। इस करोड़ों की हेराफेरी में दोषियों के विरुद्ध जांच और एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आज थाना में ज्ञापन सौंपने आए। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के इस कदम के बाद प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।

अवैध रेत उत्खनन, रेत परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार कार्यवाही

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा ज़िले में रेत के अवैध उत्खनन-परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम की कार्यवाही की गई। जाँच के दौरान ग्राम हरदीडीह तहसील आरंग से एक चैन मशीन जब्त किया गया, जिसे थाना आरंग में रखा गया।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम चम्पारण तहसील नवापारा में जाँच के दौरान मशीन चालक द्वारा मशीन को नदी की दूसरे छोर जो कि गरियाबंद ज़िले में आता है, में ले जाकर छिपाया गया था जिसे गरियाबंद ज़िले के खनिज अमला के सहयोग से एक मशीन जब्त किया। थाना गोबरा नवापारा में रखा गया व एक मशीन ग्राम कोटवार ग्राम परसदा जोसी, गरियाबंद के अभिरक्षा में दिया गया।ग्राम कुम्हारी तहसील आरंग के रेत घाट में एक मशीन लगे पाये जाने पर उसे जप्त कर थाना आरंग में रखा गया। ग्राम कागदेही के रेट घाट में 01 मशीन लगे पाये जाने पर जप्त कर थाना आरंग में रखा गया है ।जाँच के दौरान खनिज के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 04 वाहनों को प्रकरण दर्ज कर थाना गोबरानवापारा में, 04 वाहन मंदिर हसौद थाने में एवं 03 वाहनो को प्रकरण दर्ज कर थाना आरंग में रखा गया है। 24 घंटों में ज़िला रायपुर अन्तर्गत कुल 05 मशीनों एवं 11 हाईवा के ऊपर अवैध उत्खनन/परिवहन की कार्यवाही करते हुए रेत खनन का कार्य पूर्णतया बंद कराया गया है, व भविष्य में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा राजस्व एवं पुलिस विभाग के साथ मिलकर सतत कार्यवाही एवं निगरानी की जा रही है।

कोल डिस्पेच में लगी ठेका कंपनी कर रही मजदूरों का शोषण

सैकड़ों कर्मचारियों ने बंद किया काम

कोरबा। कोयला खदानों में ठेका मजदूरों के साथ हो रहे शोषण पर कोई ठोस समाधान होता नहीं दिख रहा है। ठेका कंपनिया केवल आश्वाशन रूपी जुमला इस्तेमाल कर अपना काम निकाल रही हैं। ऐसी ही एक ठेका कंपनी एसईसीएल कुसमुंडा खदान में कोल डिस्पेच का काम कर रही जय अम्बे रोड लाइन है, जिस पर मजदूरों ने शोषण का आरोप लगाया है। कंपनी द्वारा एचपीसी दर पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा महीने भर काम करने के बाद भी उन्हें पेमेंट समय पर नहीं दिया जा रहा है।

कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सेफ्टी के लिए ना ही जूते दिए गए हैं और ना ही टोपी। यहां तक की उनका बीफॉर्म भी नहीं है। बावजूद इसके उनसे काम लेकर उनके साथ शोषण किया जा रहा है। इन्हीं समस्याओ को लेकर जय अम्बे कंपनी के कर्मचारी आज एसईसीएल कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में जय अम्बे कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

भूविस्थापित अशोक कुमार ने बताया कि कई बार हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सेफ्टी बेल्ट नहीं होने के कारण कर्मचारियों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया गया और पत्र लिखकर उन्हें अवगत भी कराया गया था, निजी

कंपनी की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं इसमें एसईसीएल प्रबंधन भी दोषी है। ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर हटा दिया यह जानना चाहिए।

कुछ देर बाद एरिया महाप्रबंधक राजीव सिंह अपने चेंबर से बाहर निकलकर ठेका मजदूरों से मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी ठेका मजदूरों की बात सुनी और मौके पर जय अम्बे कंपनी के अधिकारियों को बुलाया और कर्मचारियों को हो रही समस्याओं को दूर करने की बात कही, जिस पर जय अम्बे कम्पनी के अधिकारी कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जीएम ने भी मजदूरों से कहा कि जब तक जय अम्बे कंपनी तय वेतनमान में भुगतान नहीं करती आप लोग काम बंद रख सकते हैं। इसके बाद मजदूर जीएम कार्यालय से निकल गए। सभी मजदूरों ने अपनी बात पूरी नहीं होने तक काम बंद करने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ में मिनी माल वाहन के खाई में गिरने से 2 सीएएफ कर्मियों की मौत

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मिनी माल वाहन के खाई में गिर जाने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के दो कर्मियों की मौत हो गई, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बुधवार देर शाम हुई इस दुर्घटना में सीएएफ का एक जवान और वाहन का चालक, जो एक नागरिक है, भी घायल हो गया।

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि जब यह घटना झारखंड राज्य की सीमा से लगे पुंदाग और भुतही गांवों के बीच हुई, तब सीएएफ कर्मी अपने शिविर को स्थानांतरित करने में लगे हुए थे।

सीएएफ की 10वीं बटालियन की डी कंपनी को जिले के रामचंद्रपुर से पुंदाग स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुनर्नियुक्ति अभ्यास के तहत सुरक्षा कर्मियों, सामान और अन्य सामग्रियों को बसों और ट्रकों में शिविर के नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि परिवहन में लगा एक बड़ा ट्रक बंदरचुआ गांव से आगे नहीं जा सका, इसलिए ट्रक में लदे सामान को वहां से नए कैंप स्थान तक ले जाने के लिए एक छोटी गाड़ी लगाई गई। एक बार सामान ढोने के बाद, जब वाहन का चालक पहाड़ी पर एक तीखे मोड़ से निपटने में विफल रहा, तो वाहन एक और चक्कर लगाने लगा। अधिकारी ने बताया कि वाहन एक खाई में गिर गया और एक पेड़ से जा टकराया।

सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश के निवासी हेड कांस्टेबल फतेह बहादुर और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कांस्टेबल नारायण प्रसाद की इस घटना में मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल राप्रताप सिंह और नागरिक चालक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

कोंडागांव के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में जीते 12 मेडल

कोंडागांव। जिले के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 12 मेडल जीत कर जिले का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों को आईटीबीपी के जवानों ने प्रशिक्षण देने के बाद भिलाई में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से कोंडागांव के 12 खिलाड़ी पदक हासिल करने में सफल रहे। इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी जूडो ट्रेनिंग कैंप कोंडागांव से 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिसमें 06 स्वर्ण, 02 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए।

सब जूनियर कैटेगरी में लिलेश्वरी को गोल्ड मेडल सब जूनियर 28 किलोग्राम कैटेगरी में लिलेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता। 36 किलोग्राम में ममता ने रजत पदक, 48 किलोग्राम में चंद्रप्रभा ठाकुर और 66 किलोग्राम में मयंक खांडेकर ने कांस्य पदक जीता। जूनियर वर्ग की बात करें तो 30 किलोग्राम वर्ग में वेदांत ठाकुर, 40 किलोग्राम वर्ग में विशिष्टका और 52 किलोग्राम वर्ग में लेखा नेताम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 48 किलोग्राम वर्ग में गीता हिडको, 55 किलोग्राम वर्ग में काधिर हुसने, 60 किलोग्राम वर्ग में अनिल गोठा ने पदक हासिल किए। सीनियर कैटेगरी में 66 किलोग्राम वर्ग में प्रदीप बघेल ने गोल्ड मेडल जीता। 48 किलोग्राम वर्ग में शिवानी नेताम ने कांस्य पदक हासिल किया।

उक्त सभी खिलाड़ी पिछले कई सालों से आईटीबीपी के प्रशिक्षक उदय सिहं यादव और नारायण सोरेन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर राणा युद्धवीर सिंह, उप महानिरीक्षक और नरेन्द्र सिंह सेनानी (आईटीबीपी) ने सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को लगातार इसी प्रकार प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हाथियों का आतंक जारी, वन क्षेत्र के घरों में मचाई तबाही

■ जान बचाकर भागे ग्रामिणों ने आश्रम में गुजारी रात

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का आतंक जारी है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों घरों को तोड़कर हाथियों ने क्षति पहुंचाई है, जिससे पहाड़ी कोरवाओं के बस्ती में दहशत फैल गई है।

बीती रात, मोहनाडीहारी उड़मकेला में पहाड़ी कोरवाओं की बस्ती में 13 हाथियों ने तबाही मचाई। अपनी जान बचाने के लिए लोग भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। पहाड़ी कोरवाओं को उड़मकेला आश्रम में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने रात बिताई।

वन विभाग ने स्थिति को देखते हुए मुनादी की है, जिससे लोगों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को सतर्क रहने और हाथियों के निकट नहीं जाने की सलाह दी है।

यह घटना सरगुजा में हाथियों के आतंक का ताजा उदाहरण है, जिससे स्थानीय निवासियों को जान-माल का

भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों के बावजूद हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि वे हाथियों को नियंत्रित करने और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

इस घटना से प्रभावित लोग बेहद परेशान हैं और प्रशासन से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्रों में वापस भेजने के प्रयास जारी हैं ताकि लोगों की जान-माल की रक्षा की जा सके।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पीएम जनमन शिविर में अनुपस्थित रहे खाद्य निरीक्षक

गौरेला पेंड्रा मरवाही। निलंबन आदेश में कहा गया है कि 14 जून 2024 को गौरेला ब्लॉक के ग्राम देवरगांव में आयाजित पीएम जनमन शिविर में अनुपस्थित पाए जाने एवं अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण खाद्य निरीक्षक जितेंद्र वासुदेव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-6 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के तहत बैगा जनजाति के लोगों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाना है। इसके लिए गौरेला विकासखंड के बैगा बहुल 13 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर छूटे हुए सभी बैगा परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत कनेक्शन, उज्जवला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि से लाभान्वित किया जा रहा है।

गुटोली के निस्तारी तालब से पकड़ा गया मगरमच्छ

दंतेवाड़ा। जिले के गुटोली गांव के निस्तारी तालब से वन विभाग की टीम ने एक वयस्क मगरमच्छ के बड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर इंद्रावती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मगरमच्छ गांव के तालाब में घुस गया था, इसकी जानकारी गीदम वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक मात्र तालाब है, जिस पर पूरा गांव निर्भर है। कुछ दिन पहले इस तालाब में एक मगरमच्छ को देखा गया था। जिसके बाद से गांव के लोग तालाब के नजदीक जाने से डरते थे। गांव वालों का कहना है कि, इससे पहले भी गांव में तालाब-डबरी में मगरमच्छ देखे गए थे। पास की ही नदी-नालों से निकलकर खेतों से होते हुए मगरमच्छ तालाब तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल एक ही मगरमच्छ देखा गया था जिसे वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर इंद्रावती नदी में छोड़ दिया है।

बिलासपुर एवं अमृतसर के मध्य स्पेशल ट्रेन की सुविधा

बिलासपुर। रेल यात्रियो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा एक द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 08293/08294 बिलासपुर-अमृतसर-बिलासपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर एवं अमृतसर के मध्य 05 फेरो के लिये चलाई जायेगी। इससे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, डोंगरगढ़ सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के रेल यात्री लाभान्वित होंगे। यह गाड़ी बिलासपुर से प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को ट्रेन नंबर 08293 बिलासपुर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25, 29 जून, 02, 06 एवं 09 जुलाई, को तथा इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी अमृतसर से प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को ट्रेन नंबर 08294 अमृतसर-बिलासपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 जून, 01, 04, 08 एवं 11 जुलाई, को चलेगी। इस द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 06 सामान्य, 10 स्लीपर, 01 एसी थ्री, 01 एसी-टू श्रेणी सहित कुल 20 कोच रहेगी।

जलावर्धन योजना में भारी अनियमितता

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पथरिया नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले जल आवर्धन योजना में हुए 69 लाख के घोटाले पर राज्य स्तरीय टीम द्वारा की गई जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, सीएमओ ने पुलिस में आवेदन कर नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सीएमओ और इंजीनियर के खिलाफ योजना के अंतर्गत बड़ी अनियमितता की शिकायत की थी और साथ ही योजना में जांच समिति की रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसके अनुसार आरोपियों ने जलावर्धन योजना के अंतर्गत 4 जून 2020 से 15 महिने के अंदर पाईप लाईन बिछाने के कार्य को अब तक पूरा नहीं किया। इसके साथ ही तीनों ने मिलकर 69 लाख रुपये का घोटाल किया है। वर्तमान सीएमओ की शिकायत के बाद राज्य स्तरीय टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सीएमओ और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कावानार से विस्फोटक के साथ नक्सल सामग्री बरामद

नारायणपुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मलन अभियान के तहत कैम्प कड़ेनार से डीआरजी एवं 45वीं वाहिनी आईटीबीपी की संयुक्त बल बुधवार को एरिया डॉमिनेशन पर ग्राम कावानार-तोयमेटा की ओर रवाना हुई थी। सुरक्षा बल कावानार बस्ती के अंदर पहुंची तो सोलर प्लेट के बैटरी रखने के लिए बने कमरे से 11 नग कुकर, 02 नग प्लास्टिक ड्रम, 01 नग स्टील ड्रम, बिजली वायर, फटाका, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, बैटरी सेल, इनवर्टर, बर्तन, नक्सली बैनर एवं भारी मात्रा में अन्य नक्सल सामग्री मिला। नक्सलियों के द्वारा उक्त कुकर, टिफिन, बिजली वायर, कोडेक्स, डेटोनेटर, फटाका एवं अन्य सामग्री का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एकत्रित कर रखा गया था। जिसे सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के नापाक मनसुबे को विफल करते हुए बरामद कर आज सुबह सुरक्षित कैंप वापस पंहुच गये। उक्त कार्यवाही में जिला पुलिस बल, डीआरजी एवं आईटीबीपी का विशेष योगदान रहा।

आधार कार्ड बनवाने एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं ग्रामीण

बीजापुर। जिले के नक्सल प्रभावित नेशनल पार्क एरिया के सेड्रा, एड़ापल्ली, बड़ेकाकलेड पंचायत के बड़ी संख्या में ग्रामीणों के आधार कार्ड नहीं बने हैं। भोपालपटनम ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि राशन व दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा आधार कार्ड के अनिवार्य किए जाने के बाद ग्रामीण आधार कार्ड बनवाने आये हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आधार कार्ड बनवाने की कोई व्यवस्था नहीं होने कि वजह से उन्हें 70 किमी पैदल सफर तय कर ब्लॉक मुख्यालय भोपालपटनम पंहुचे हैं, लेकिन यहां सीएससी सेंटर बंद होने से एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं।

ग्राम पंचायत सेंड्रा के लक्ष्मी मेट्टा, समक्का कुरसम, चिड़ेम मासे, इरपे मेट्टा, रेहान कुम्मा, पुष्पा मंडरा, सरस्वती मंडरा, पुष्पा पालदेव, कुमा बिचाबाई, पुनेम शांता, गायत्री गुरला,

छोड़े बच्चे- रितिक पालदेव, अजय पालदेव, कार्तिक मड़े, मड़े अश्वनी, कुरसम रितिक, पूजा कुरसम, रोहिणी मेट्टा ने बताया कि बीते 13 जून से सेंड्रा, बड़ेकाकलेड ,एडापल्ली पंचायत के दर्जनों ग्रामीण अपने दुधमुहे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को लेकर आधार कार्ड बनवाने आये हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वो सीएससी के चक्कर काट रहे हैं। भोपालपटनम में तीन सीएचसी सेंटर है, जहां आधार कार्ड बनाया जाता है। एक संस्थान बंद है और एक स् का ऑपरेटर नहीं है और एक के पास टेक्निकल परेशानी की वजह से इनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस दौरान वे सभी ग्रामीण भेपालपटनम में बसे अपने रिश्तेदारों के यहां रुकना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि गांव मे अधिकतर ग्रामीणों के पास आधार कार्ड नहीं होने की वजह से वे कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

स्थानीय पत्रकारों ने ग्रामीणों की समस्या से अवगत होने के बाद गुरूवार को इसकी सूचना जनपद पंचायत भोपालपटनम के सीईओ दिलीप उइके को दी। सीईओ दिलीप उइके ने तत्काल सीएचसी सेंटर पहुंचकर उन ग्रामीणों की समस्या को जाना और उन पंचायतों के सचिवों को बुलाकर फटकार लगाई। पास में पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बनवाने का सुझाव दिया। उन्होंने ग्रामीणों को बालक आश्रम में रुकवाने और भोजन की व्यवस्था करवाने सचिवों को निर्देश भी दिए हैं।

अनाधिकृत वेंडर पकडे गये, जुर्माने की गई कार्रवाई

अनाधिकृत वेंडरों की रोकथाम हेतु बिलासपुर स्टेशन व ट्रेनों में चलाया जा रहा विशेष जांच अभियान

बिलासपुर। रेलवे द्वारा अधिकृत वेंडरों द्वारा गाडियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। रेलवे प्रशासन स्टेशनों एवं गाडियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार हेतु प्रयासरत है। साथ ही रेलवे प्रशासन को अनाधिकृत वेंडिंग की शिकायत भी समय-समय पर मिलती है। इसी संदर्भ में वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के निर्देश पर मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा गाडियों तथा प्रमुख स्टेशनों में अनाधिकृत वेंडरों की रोकथाम हेतु निरंतर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में 18 व 19 जून को मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री एस भारतीयन के नेतृत्व

में बिलासपुर स्टेशन में चलाये गए जांच अभियान के दौरान 28 आनाधिकृत वेंडर पकडे गये जिन पर रेलवे नियमानुसार 24,585 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, टिकट चेकिंग स्टाफ व आरपीएफ़ स्टाफ भी शामिल थे। इसके अलावा बिना प्लेटफार्म परमिट के किसी भी वेंडर को प्लेटफार्म एवं गाडियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचे जाने बावत सख्त हिदायत सभी केटरिंग संचालकों को दी गई । मंडल रेल प्रशासन अनाधिकृत वेंडिंग को पूर्णत- बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा।

रेलवे ने यात्रियों को आगाह किया है कि जुर्माने की कार्यवाही से बचने उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतिक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत नहीं है। यात्रा से पूर्व अपने सामान को बुक कराएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

संक्षिप्त समाचार

भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का पलटवार

तखतपुर। प्रथम नगर आगमन पर तखतपुर में

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव का कद छोटा करने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर तोखन साहू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, एक दूसरे का कद छोटा करना कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को जोड़कर चलते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने कहा, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का पंच से लेकर लोकसभा तक पहुंचना और मोदी के मंत्री मंडल में शामिल होना भाजपा में ही संभव है। भूपेश बघेल इस तरह की बाते करके कांग्रेस पार्टी की संस्कृति को बता रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही भाजपा पार्टी का मूलमंत्र है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर पहुंचे तोखन साहू का जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और सभी समाज के लोगों ने तोखन साहू को हार माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर केंद्रीय मंत्री बनाने की खुशी जताई।

लोक आयोग के दफ्तर में लगी आग मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के दफ्तर में गुरुवार दोपहर आग लग गई। नगर निगम के पास स्थित लोक आयोग के दफ्तर को आग लगते ही खाली कराया गया। सूचना पर मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंच गई है, और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री साय से निवेशकों ने की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव

साय से मंत्रालय भवन में निवेशकों ने मुलाकात की है। निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की रूचि दिखाई है। इन निवेशकों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलिपरफॉर्मेंस शामिल हैं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना और नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रूचि दिखाई है। कंपनी की योजना जशपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेलिपरफॉर्मेंस कंपनी आईटी एवं आईटीज के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, जिसने नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रूचि दिखाई है। सीएम साय ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल बढ़ाई जाए और उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाईयों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। ऐसे उद्योगों को प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे प्रदूषण नहीं हो। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां निवेश करना निवेशकों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निवेशकों ने भी नवा रायपुर में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री सहित मंत्रिगणों ने सांसद बनने पर बृजमोहन को किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की

अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री बृजमोहन अग्रवाल को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री अग्रवाल को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा की वे सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इस बार उन्होंने रिकार्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री अग्रवाल को सम्मानित किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

20 हजार से अधिक गांवों में भू-सर्वे को बनाया जा रहा है त्रुटि रहित

अब तक 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो-रिफेरेसिंग कार्य पूर्ण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफेरेसिंग एवं डिजिटाइजेशन परियोजना भी संचालित की जा रही है। जिसमें राज्य का सम्पूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित हो जाएगा और एक डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा सकेगा। यह जियो रिफ्रेंसिंग कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण से किया जा कर सैटेलाईट ईमेज से किया जा रहा है।

राज्य में संचालित की जा रही कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफेरेसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में भूमि का सर्वेक्षण का काम होगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, कोरबा सहित 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो रिफ्रेंसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक जियो रिफेरेसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक में छोटी से छोटी

भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दी गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जियो रिफेरेसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना में राज्य का सम्पूर्ण हिस्से का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम की सीमा का सेटेलाईट इमेज पर त्रुटि रहित चिन्हांकन होगा। इससे प्रत्येक ग्राम का राजस्व अभिलेख की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।

परियोजना के माध्यम से भू-सर्वे का कार्य त्रुटि रहित होने के साथ-साथ बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरणों का तेजी से निराकण किया जा सकेगा। सीमांकन कार्य में भूमि संबंधी विवादों का सही-सही निराकरण किया जा सकेगा। जियो-रिफेरेसिंग कार्य से वर्तमान में उपलब्ध पटवारी नक्शा तथा स्थल पर भिन्नता का आंकलन कर उनका निराकरण भी किया जा सकेगा। सीमांकन-नामांतरण, बटवारा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री गति सक्ती योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और जल संसाधन आदि विभागों की परि-सम्पत्तियां को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा।

भू-सर्वे सत्यापन की प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, कलेक्टर को सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी के मार्ग-दर्शन में उप-सर्वेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार कार्य करेंगे। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कलेक्टर के परिवेक्षण में तथा एसडीएम, तहसीलदार के निर्देश में जारी प्रपत्र अनुसार सत्यापन कर नक्शे एवं स्थल के मध्य की भिन्नता को दूर करेंगे।

पटवारियों द्वारा ऐसे 15-20 अनडिस्प्यिूड ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंटस को मिलान किया जाएगा जो खसरा मैप और सेटेलाईट इमेज में समान रूप से मिलते हैं। जियो-रिफेरेसिंग खसरा नक्शों में खसरा नंबर मूल पटवारी नक्शों से मिलान किया जाएगा, प्रत्येक खसरा के रिकॉर्ड एरिया एवं जीआईएस एरिया का मिलान किया जाएगा, ग्राम के सीमा से लगे अन्य ग्रामों की सीमा की ओवरलेपिंग एवं गेप की जांच एवं निराकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के साथ 35 हजार से अधिक लोग आज करेंगे योग

राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशम् संस्करण के अवसर पर 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग करेंगी। मुख्यमंत्री साय 35 हजार से अधिक लोगों के साथ एक साथ योग करेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 7 से 8 बजे तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षित एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास का प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। जिसमें राज्य के जन-प्रतिनिधिगण, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं पंतजलि योग संस्थान छत्तीसगढ़, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी संस्थान छत्तीसगढ़, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान छत्तीसगढ़, अखिल भारतीय गायत्री परिवार संस्थान छत्तीसगढ़, हार्टफुलनेंस योग संस्थान छत्तीसगढ़, हास्य योग संस्थान छत्तीसगढ़ के योग साधक सहित लगभग 35 हजार जन सामान्य सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व की प्राचीनतम् विधा योग को जन समान्य के दिनचर्या का अंग बनाना एवं राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवनशैली एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग से परिचित कराना तथा प्रतिदिन योगाभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ-साथ योग के माध्यम से नशामुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उक्त कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है।

वित्त मंत्री चौधरी जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में होंगे शामिल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार 21 जून को आयोजित जांजगीर-चांपा जिला के योग

कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है।

धमतरी के योगाभ्यास कार्यक्रम में खेल मंत्री वर्मा होंगे शामिल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 21 जून को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंक राम वर्मा जिला मुख्यालय धमतरी के हरदिहा साहू समाज भवन में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि योग को हर गांव-शहर तक पहुंचने

का संदेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 21 जून 2024 को सुबह 6:30 बजे से धमतरी के हरदिहा साहू समाज भवन से सामूहिक योग अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है।

योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री केदार कश्यप

नारायणपुर। 21 जून को दशम् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन क्रिड़ा परिसर खेल मैदान नारायणपुर में प्रातः 07 बजे से योग कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित होंगे।

इस हेतु सभी विभागो की सहभागीता सुनिश्चित किए जाने यह आवश्यक है। कलेक्टर श्री बिपिन मांझी द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्यालय प्रमुख को अपने विभाग के अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ 21 जून 2024 को प्रात 06.30 बजे क्रिड़ा परिसर खेल मैदान में उपस्थित होने निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप होंगे।

रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग ठेकेदार की मनमानी पर थमे ऑटो के पहिए

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग ठेकेदार द्वारा शुल्क लिए जाने के विरोध में ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया है। प्री-पैड ऑटो यूनियन ने इसके साथ ही स्टेशन अधीक्षक और ष्ठक्रू का घेराव करने की योजना बनाई है। ऑटो के पहिए थमने से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है।

ऑटो चालक ने बताया कि पिछले कई सालों से रायपुर रेलवे स्टेशन में सवारी ऑटो चला रहे है। लेकिन कभी कोई शुल्क नहीं लिया गया। लेकिन अब सभी ऑटो चालकों से शुल्क लिया जा रहा है। चाहे ई-रिक्शा हो या सवारी ऑटो सभी से 20-20 रुपए शुल्क लिया जा रहा है।

ऑटो चालकों का कहना है कि हम जितने बार भी ऑटो स्टेशन परिसर के अंदर ले जाते हैं। उतने बार पार्किंग स्टाफ हमसे 20 रुपए बतौर शुल्क मांगता है। इसी वजह से आज हमने हड़ताल किया है। लगभग 300 ऑटो के पहिए रुके हुए हैं। आम जनता भी परेशान हो रही है। हम नहीं चाहते कि कोई आम जनता परेशान हो, लेकिन मजबूरी है।

महिला ऑटो चालक ने कहा कि इतनी महंगाई में दो वक्त का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हर राउंड में 20-20 रुपए शुल्क लिया जाएगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ऑटो चालक में कहा कि यहां के बाद हम ष्ठक्रू ऑफिस जाकर उनसे बातचीत करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और तो उचित निर्णय लेंगे।

धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। आगामी विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की आरंभिक तैयारी की समीक्षा की गई। मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में धान उपार्जन हेतु बारदाने की व्यवस्था और किसान पंजीयन खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में खाद्य विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., कृषि विभाग की सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव राजस्व श्री अविनाश चंपावत, सचिव सहकारिता श्री सी.आर.प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य श्री के.डी.कुंजाम, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री रमेश शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग का मरम्मत कार्य नही होने पर

विधायक ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने दिये निर्देश

कोंडागांव। जिले के केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम केशकाल नगर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में जगह जगह हुऐ गड्ढों का मरम्मत कार्य नही किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को समय पर काम नही करने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त कर जमा सुरक्षा निधी जप्त करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट घोषित कर विभाग द्वारा अविलम्ब गुणवत्तायुक्त मरम्मत कार्य करवाने कहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी के साथ गुरुवारे को विधायक नीलकंठ टेकाम ने केशकाल घाटी मार्ग का अवलोकन किया और मार्ग में बन चुके बड़े बड़े गड्ढों एवं उखड़ चुके सड़क की तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा की जब अभी गर्मी में सड़क का ये हाल है, तो आने वाले बरसात में कितना बुरा हाल हो जायेगा । आये दिन दुर्घटना होगी गाडियां खराब होगी और जाम लगेगा लोगों को परेशान होना पड़ेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? उन्होने कहा कि शासन प्रशासन एवं विभाग को इस ओर बहुत गंभीरता से गौर करते मार्ग मरम्मत एवं निर्माण के स्वीकृत कार्य को अटकाए रखने वाले ठेकेदारों पर प्रभावी कार्रवाई करना होगा तभी स्थिति में सुधार आ पाना संभव होगा।

केशकाल विधायक विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के वर्षों से अटके पड़े बाईपास सड़क निर्माण कार्य चालू करवाने के लिए दो सप्ताह पूर्व 7 जून को विभागीय अधिकारियों को सांथ लेकर केशकाल घाटी के बाईपास मार्ग के लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर निर्माणाधीन सडक का अवलोकन किया था और अधिकारियों उस वक्त भी हिदायत दिया था, कि जल्दी से जल्दी बरसात चालू होने के पहले मरम्मत करा दिया जावे, बावजूद इसके राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत का काम चालू तक नहीं किया गया। घाटी में अक्सर लगने वाले जाम की स्थिति से लोगों को मुक्ति दिलाने और केशकाल नगरवासियों को धूल किचड़ से राहत दिलाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है।

शिवसेना मनाया 58वां स्थापना दिवस

रायपुर। महोबा बाजार चौक पर शिवसेना छत्तीसगढ़ महिला सेना ने 58वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रसाद के रुप में शरबत व फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ना केवल पार्टी के स्थापना दिवस को मनाना था बल्कि इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उनके आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करना भी था।

शिवसेना महिला सेना की प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सिंह ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया, हम भी उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को संकल्प दिलाया कि वे शिवसेना पार्टी को राज्य में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। महासचिव कोमल तिवारी ने कहा कि यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

धान के एमएसपी में केंद्र के बाद क्या राज्य सरकार करेगी वृद्धि?

डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया जवाब

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ धान के एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। जब इनकी सरकार थी, तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है।

वहीं हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस के समीक्षा टीम का गठन किए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक नेतृत्व विहीन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का अपना अंदरुनी काम है। समीक्षा करें, जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस केवल एक परिवार के पार्टी बनकर रह गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद-बीज की आपूर्ति को लेकर कहा कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। गुणवत्ता विहीन काम और काम में लापरवाही पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन उप अभियंताओं और लेखपाल के निलंबन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां पर भी अनियमित, लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों और कई विभागों में अलग-अलग आयोजन किए हैं। योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मंत्रीगण अलग-अलग जिलों के कार्यक्रम में रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में अलग-अलग आयोजन निर्धारित किया है।

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर रोड, नाली, पानी, डामरीकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्वीकृति काम को शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही जल्द काम शुरू नहीं होने पर विधानसभा के मानसून सत्र में इन मुद्दों को उठाने की बात कही।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-धमतरी (छग)

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

Email ID-eedha-phe-cg@nic.in, Telephone no. 07722 238719

निविदा क्रमांक - 01/ले.शा./का.अ./ लोस्वायांखंड/2024-25 दिनांक 15/06/2024

मुहरबंद निविदायें नीचे उल्लेखित कार्य हेतु प्रपत्र 'ए' प्रतिशत दर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, ई-पंजीयन प्रणाली की 'द' एवं उच्च श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों से स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है-

कार्य का विवरण- राज्यमद अंतर्गत धमतरी जिले विभिन्न विकासखण्ड के ग्रामों में नवीन 'वी' वायर तकनीक के माध्यम से भूमिगत जल/पेयजल बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए इंजेक्शन कुंआ का कार्य। (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित)

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 04.07.2024 सायं 5.30 बजे तक

स. क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
01	02	03	04
01	धमतरी कुरूद	बोड़रा (स), बिजनापुरी, बेन्द्रानवागांव डांडेसरा	17.28
02	कुरूद	कल्ले, सिरीं, कोड़ापार एवं नवागांव (थू)	17.28

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
धमतरी (छग)

जी- 242500398/5

ज्ञान के अविरल प्रवाह का नाम है नालंदा

प्रो. रवींद्र

लगभग एक दशक पहले स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के नये भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक विकास यात्रा है। 'नालंदा' सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, गौरव है, सम्मान है। आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं। उनका संकेत श्री नालंदा महाविहार के पुस्तकालय को जलाये जाने की ओर था। ज्ञान हृदय का उजाला है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारा अभीष्ट रहा है। नालंदा एक नयी शुरुआत कर सकता था। उसने यही किया है। विश्व में आज विद्या व ज्ञान के माध्यम से नालंदा भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। वह यह भी बतायेगा कि हम मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भविष्य की नींव रखना जानते हैं। अब नालंदा विश्व के अतीत ही नहीं, भविष्य को भी उद्घाटित करेगा। नालंदा ज्ञान के अविरल प्रवाह का नाम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आरंभिक वैश्विक आधारशिला है बिहार। इस बहाने भी संसार में लोकतंत्र के प्रसार का संदेश जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नालंदा क्षेत्र पांच धर्मों का केंद्र है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का संदेश विश्व में सहमति एवं असहमति के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक समय में भी नालंदा विद्या व संस्कृति के नये केंद्र के रूप में उभरा है। इसमें दक्षिण एशिया व विश्व को नयी समझ, शांति व मनुष्यता को विकसित करने की अपार क्षमता है। यह उसके अतीत से आता है। नालंदा विश्व का ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध था। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा की व्यवस्थित व वैज्ञानिक प्रणाली का विकास संभव हुआ था। तब विश्वविद्यालय शब्द चलन में नहीं था। इसके लिए अमूमन महाविहार शब्द प्रयुक्त होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को श्री नालंदा महाविहार के रूप में जाना जाता था। नालंदा विचार के साथ-साथ साहित्य का केंद्र भी था। यह कम लोगों को ज्ञात है कि नालंदा में हिंदी कविता का जन्म हुआ। यह अपभ्रंश के रूप में हुआ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, सरहपा हिंदी कविता के प्रथम कवि थे। उनकी रचना 'दोहा कोश' राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत में अनूदित मिली, जिसका अपभ्रंश में रूपांतरण उन्होंने किया। एक नयी दृष्टि, भाव बोध व काव्य व्याकरण को जन्म देने का श्रेय सरहपा की रचना को जाता है। सरहपा की जैसी चर्चा नालंदा के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। कोई पीठ, मार्ग, भवन, चौराहा तक नहीं है उनके नाम पर। कथ्य है कि राहुल श्रीभद्र यानी सरहपा प्राचीन श्री नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम दिनों में आचार्य थे, उसके बाद यह धरोहर में तब्दील हो गया। गुप्त काल में विकसित उदार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं नालंदा के बहुविषयक शैक्षणिक पाठ्यक्रम का मूल आधार बनीं, जिसमें बौद्धिक बौद्ध धर्म को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च ज्ञान के साथ मिश्रित किया गया। नालंदा आरंभ से ही जैन, बौद्ध व सनातन का समन्वित केंद्र रहा है। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। महाभारतकालीन अवशेष, जरासंध का अखाड़ा, विश्वस्तरीय मलमास मेला, गर्म जल का कुंड, गया में पितरों का विसर्जन आदि की सनातन परंपरा रही है। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का प्रथम बार राजगीर में स्वागत किया था। स्पष्ट है कि नालंदा केवल बुद्ध का ही आभा क्षेत्र नहीं रहा है, इसलिए नालंदा के माध्यम से केवल बुद्ध धर्म को रेखांकित करना एकांगिकता है। विचारकों में असहमति है कि पांचवीं शताब्दी में स्थापित श्री नालंदा महाविहार के बाद राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो 2014 में स्थापित हुआ, सीधे उत्तराधिकारी है। सच यह है कि नव नालंदा महाविहार, जो नालंदा में स्थित है, वह प्राथमिक रूप से 1951 में ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के सौजन्य से स्थापित हो चुका था। भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस इलाके में नया जागरण किया था। वे और प्रख्यात हिंदी लेखक व तब बिहार के शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर ने इसकी कल्पना की थी।

राजनीति में जाति का कायम है वर्चस्व

प्रभु चावला

मोदी 3.0 के नेतृत्व में, एनडीए 3.0 में जातिगत छाप स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी इसके शिल्पकार हैं जिन्होंने भारत की सामाजिक विरासत की शाश्वत भट्टी में सरकार बनाने के लिए वर्ण और कर्म को मिश्रित किया है। राम मोहन राय, विवेकानंद, सुब्रमण्यम भारती और नारायण गुरु जैसे लोगों की विरासतों के बावजूद, सुधारों में अब विकृति आ गई है। जाति हमारी आधुनिक आकांक्षाओं पर अपनी छाया डालती है। इसकी सामाजिक विकृति में हालांकि कमी आई है, लेकिन चुनाव दर चुनाव इसका राजनीतिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब योग्यता को नहीं, बल्कि जाति को महत्व देकर सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। पिछले हफ्ते जब दिल्ली, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा में नई सरकारें बनीं तो चर्चा उम्मीदवारों की जाति को लेकर थी, न कि जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी उपलब्धियों की। लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निरंतरता और बदलाव के आदर्श मिश्रण के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जाति को दिए जाने वाले इस अत्यधिक महत्व के आगे मंत्रियों की योग्यता गौण हो गई है और उनकी राजनीतिक स्थिति में भी गिरावट आई है। राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जाति को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में दिखाना भारत के बढ़ते राजनीतिक बाजार में जीत की सबसे अच्छी रणनीति बन गई है। उदाहरण के लिए, पिछले हफ्ते ओडिशा में भाजपा ने करिश्माई नवीन पटनायक को सत्ता से बेदखल करके बड़ी जीत हासिल की, जो 24 साल से सत्ता में थे।

निस्संदेह, भाजपा ने आंशिक रूप से उड़िया अस्मिता या गौरव का आह्वान करके जीत हासिल की क्योंकि एक पूर्व दक्षिण भारतीय नौकरशाह सत्ता पर राज कर रहा था और उसे पटनायक का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ से लेकर मोदी तक, भाजपा का सबसे बड़ा सवाल यही था, ''क्या आप एक तमिल बाबू को ओडिशा पर शासन करने देंगे?'' जब राज्य में अपना पहला मुख्यमंत्री चुनने का समय आया, तो पार्टी ने उपलब्धियों के बजाय सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखा। 52 वर्षीय आदिवासी मोहन चरण माझी को ओडिशा के पहले भगवा मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। राज्य के अनोखे सामाजिक गणित को साधने के लिए, पिछली गठबंधन सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री के.वी। सिंह देव को दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक के रूप में शपथ दिलाई गई। दूसरी, प्रवती परिदा महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा की प्रतीक हैं और राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री हैं। इन नियुक्तियों में भाजपा के कई दिग्गजों को किनारे कर दिया गया, क्योंकि वे राज्य की नई भगवा सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं थे। प्रथम दृष्टया के.वी। सिंह देव मुख्यमंत्री बनने के लिए उपयुक्त थे।

लेकिन माझी एक साधारण सामाजिक स्थिति वाले कट्टर हिंदू के रूप में अधिक वांछनीय प्रतीत हुए होंगे। उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक दौड़ में जीतने वाले घोड़े के रूप में देखा जा रहा है। जब से मोदी पार्टी और सरकार में सबसे शक्तिशाली बने हैं, तब से दोनों पर उनका प्रभाव स्पष्ट है। स्वयं साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मोदी स्वाभाविक रूप से ऐसे अप्रत्याशित उम्मीदवारों को सामने लाते हैं, जो क्षेत्र और समाज में लंबे समय से राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं। हर राज्य में वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करने की उनकी दीर्घकालिक नीति का नवीनतम उदाहरण ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल की एक खासियत यह रही है कि उन्होंने परंपरा को तोड़ा है। जरूरी नहीं है कि अब सबसे वरिष्ठ विधायक या किसी अच्छे संपर्क वाले राजनेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए। 1980 से अब तक भाजपा के 54 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें से करीब 20 का चयन प्रधानमंत्री की सहमति से किया गया। वे सभी न केवल अपने पूर्ववर्तियों से युवा थे, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना में भी भिन्न थे। मोदी द्वारा राज्य सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुने गए सभी लोग अपने आप में एक संदेश हैं। अपेक्षाकृत युवा होने के अलावा, अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने कभी भी पार्टी या सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं संभाला है।

मोदी ने वरिष्ठता और प्रमुख जाति के अधिकार को नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड और ओडिशा में आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने यूपी में युवा ठाकुर योगी आदित्यनाथ को और महाराष्ट्र में ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया। वे भविष्य की भाजपा का नेतृत्व करने के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हरियाणा में, उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक उम्र के आरएसएस प्रचारक मनोहर लाल खट्टर को चुना, जो जाटों के प्रभुत्व वाले राज्य में भाजपा के पहले पंजाबी मुख्यमंत्री थे; खट्टर अब एक प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं। त्रिपुरा में, बिप्लब कुमार देब सबसे कम उम्र के सीएम बने। मोदी के सबसे भरोसेमंद युवा सहयोगी अमित शाह, जो अब दो बार के गृह मंत्री हैं, को 2019 में भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। राजस्थान के ब्राह्मण सीएम भजन लाल शर्मा राजपूत के गढ़ में पहली बार ही विधायक चुने गए हैं।

मध्य प्रदेश में अहीर समुदाय से मोहन लाल यादव ने पिछड़ी जाति के शिवराज चौहान की जगह ली। मोदी को अपने भाजपा शासित राज्यों में तीन आदिवासी मुख्यमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। मोदी-शाह की टीम भाजपा को युवा जोश से भरी एक नई वैचारिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है, लेकिन राज्यों में एक नई सत्ता संरचना भी स्थापित कर रही है। मोदी का विचार है कि अपने शासन वाले लगभग सभी राज्यों में ऐसे उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं, जो जातिगत संतुलन का हिस्सा न हों, बल्कि नेतृत्व की दूसरी पंक्ति के रूप में उभरें - एक ऐसी अवधारणा जो पिछले दो दशकों के दौरान लगभग गायब हो गई थी। सभी राज्यों के 25 उपमुख्यमंत्रियों में से 15 भाजपा के हैं, जिनमें से आधे दलित या पिछड़े समुदाय से हैं। कुछ ब्राह्मण उपमुख्यमंत्री हैं। सत्ता में जाति पहले, गुणवत्ता बाद में, का एक समान समीकरण हर जगह देखा जा रहा है। गरीबों और पिछड़े वर्गों से नया नेतृत्व तैयार करने का मोदी का प्राथमिक लक्ष्य अभी तक परिणाम नहीं दिखा सका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जबकि अधिकांश अन्य मंत्री या तो सेवानिवृत्त बाबू हैं या अपेक्षाकृत अनुभवहीन हैं। उन्हें व्यापक स्वीकार्यता पाने और वर्तमान नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य विकल्प बनने में मुश्किल होगी। चूंकि मोदी की जगह लेने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 30 से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसी की भी इतनी स्वीकार्यता नहीं है कि वे प्रधानमंत्री बन सकें। उत्तराधिकार के मामले में, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली भाजपा की स्थिति 139 साल पुरानी कांग्रेस जितनी ही खराब है, जहां गांधी परिवार के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान राजनीति में जाति का रंग भले ही गहरा हो गया है, लेकिन इसकी बनावट और स्वाद अच्छा नहीं है। समसामयिक जाति की राजनीति ने उन नींवों को मजबूत किया है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। 'जाति का, जाति से और जाति के लिए' भारतीय वोट बैंक की विशेषता है जिसका इस्तेमाल नेता ओवरड्राफ्ट के रूप में करते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-15)

गतांक से आगे...

यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से नहीं प्राप्त होता, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलता, बुद्धि तथा ज्ञान का सान्निध्य प्राप्त कर लेने से भी यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मेधा, वेदों, यज्ञों, उग्र-तपश्चर्या, सांख्यज्ञान, योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयत्नों से भी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन के द्वारा, प्रशंसा (गुरु सेवा) के द्वारा तथा व्युत्थान (सामान्य जीवन क्रम से ऊपर उठकर) के द्वारा आत्मज्ञानपरक शास्त्रों का श्रवण करता हुआ शम, दम, उपरति एवं तितिक्षा में स्थित होकर समाधिनिष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही देखता है, वही आत्म तत्त्व को प्राप्त कर पाता है। जो भी मनुष्य इस तरह से आत्मतत्त्व को जानता है, वह सभी का आत्मा हो जाता है।

इसके बाद पुनः रैक्व मुनि ने घोराङ्गिरस से प्रश्न किया कि हे भगवन! किसमें सभी प्रतिष्ठित हैं? तदनन्तर उन घोराङ्गिरस ने कहना प्रारम्भ किया कि रसातल के लोकों में सभी कुछ रहता है। यह रसातल का लोक किसमें स्थित है? तब उन्होंने कहा कि यह भू लोक में स्थित है।

यह भूलोक किसमें स्थित है? उन्होंने कहा- यह भुवः लोक में प्रतिष्ठित है। यह भुवर्लोक किसमें ओत-प्रोत है? तब उन्होंने बताया कि यह स्वर्लोक में स्थित है। यह स्वर्लोक किसमें ओत-प्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह महर्लोक में प्रतिष्ठित है। यह महर्लोक किसमें ओत-प्रोत है? (उत्तर) यह जनोलोक में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन ऋषि ने पुनः कहा-यह जनोलोक किसमें ओत-प्रोत है? (उत्तर) यह तपोलोक में स्थित है, ऐसा उन्होंने कहा। (प्रश्न) यह तपोलोक किसमें ओत-प्रोत है? उन्होंने कहा कि यह सत्यलोक में स्थित है।

क्रमशः ...

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

योगेश कुमार गोयल

शुक्रवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां उत्सव सम्पूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। वैसे तो योग को विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के चलते वर्ष 2015 में अपनाया गया था किंतु भारत में योग का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता रहा है कि पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है लेकिन साक्ष्यों की बात करें तो योग करीब पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है। 2700 ईसा पूर्व वैदिक काल में और उसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने को ही योग बताया था। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी योग का व्यापक उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही अद्वैतानुभूति योग कहलाता है। इसी प्रकार भगवद्गीता बोध में वर्णित है कि दुःख-सुख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, शीत-उष्ण आदि द्वंदों से अतीतय मुक्त होकर सर्वत्र समभाव से व्यवहार करना ही योग है।

भारत में योग को निरोगी रहने की करीब पांच हजार वर्ष पुरानी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीयों की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। सही मायनों में योग भारत के पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसका भारत सदियों से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाता रहा है, लेकिन कालांतर में इस दुर्लभ धरोहर की अनदेखी का ही नतीजा है कि लोग तरह-तरह की बीमारियों के मकड़जाल में जकड़ते गए। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में सम्पूर्ण विश्व को योग का संदेश दिया था लेकिन कुछ वर्षों पूर्व योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा योग विद्या को घर-घर तक पहुंचाने के बाद ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार संभव हो सका और आमजन योग की ओर आकर्षित होते गए। देखते ही देखते कई देशों में लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग का महत्व कई गुना बढ़ गया है।

योग न केवल कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है बल्कि मानसिक तनाव को खत्म कर आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। दरअसल यह एक ऐसी साधना, ऐसी दवा है, जो बिना किसी लागत के शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। यह मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाकर दिनभर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। माना गया है कि योग तथा प्राणायाम से जीवनभर दवाओं से भी ठीक न होने मधुमेह रोग का भी इलाज संभव है। यह वजन घटाने में भी सहायक माना गया है। योग की इन्हीं महत्ताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से आह्वान किया था कि दुनियाभर में प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाए ताकि प्रकृति प्रदत्त भारत की इस अमूल्य पद्धति का लाभ पूरी दुनिया उठा सके।

तिब्बत को लेकर अमेरिका का चीन को घेरने की तैयारी

नीरज कुमार दुबे

अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत उसने तिब्बत को लेकर एक विधेयक पारित कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस योजना को भारत का भी समर्थन है और इस आशंका के चलते चीन इस समय परेशान नजर आ रहा है। चीन को डर है कि यदि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ से तिब्बत फिसला तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है इसलिए वह अमेरिका को सीधे-सीधे और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने में जुट गया है।

लेकिन चीन की धमकियों से बेपरवाह नजर आ रहे अमेरिका ने तिब्बत को लेकर जो बड़ा फैसला किया है उस पर आगे बढ़ने के लिए वह अडिग नजर आ रहा है। यदि तिब्बत पर अमेरिकी नीति बदली तो क्षेत्र में इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचा तो चीन ने आंखें लाल कर लीं। लेकिन इसकी परवाह किये बिना नैन्सी पेलोसी ने भारत की धरती से चीन को तगड़ी चेतावनी दे डाली। हम आपको याद दिला दें कि 2022 में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान के प्रति समर्थन जताने के लिए वहां की यात्रा पर थीं तब भी चीन ने गहरी नाराजगी जताई थी और अब जब पेलोसी तिब्बत के साथ समर्थन जताने के लिए दलाई लामा से मिलने पहुँचीं हैं तब भी चीन आग बबूला हो गया है।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी ने चीन को कड़े शब्दों में दिए गए संदेश में कहा कि परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा, ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के अपने संदेश के साथ लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन

आप (चीन के राष्ट्रपति) चले जाएंगे और कोई भी आपको किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। पेलोसी की शी जिनपिंग के लिए आलोचनात्मक टिप्पणी तब आई जब वह चीनी राष्ट्रपति और दलाई लामा की आभा की तुलना कर रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलाई लामा का संदेश, ज्ञान और करुणा हमेशा बनी रहेगी। दूसरी ओर, यह धरती छोड़ने के बाद उनके (शी के) सभी काम किसी काम के नहीं रहेंगे।

हम आपको बता दें कि मैककॉल के अलावा शिष्टमंडल में अमेरिकी संसद के छह और प्रमुख सदस्य शामिल हैं जिनमें- नैन्सी पेलोसी, मैरिएनेट मिलर, ग्रेगरी मीक्स, निकोल मैलियोटैकिस, जिम मैकगवर्न और एमी बेरा शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल इसलिए धर्मशाला आया है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि अमेरिका, तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पेलोसी ने इस विधेयक के बारे में कहा है कि यह चीनी सरकार के लिए एक संदेश है कि इस मुद्दे पर हमारी सोच और समझ में स्पष्टता है।

हम आपको बता दें कि माइकल मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को हिमालयी शहर धर्मशाला पहुंचा था, जहां दलाई लामा 1960 के दशक से रह रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत के लिए स्वायत्तता पर जोर दे रही निर्वासित तिब्बती सरकार के कार्यालयों का दौरा किया और फिर दलाई लामा से मुलाकात की। मैककॉल ने बाद में मीडिया को बताया कि चीनी अधिकारियों ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को एक पत्र भेजा था जिसमें हमें यहां नहीं आने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार के मामले में उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, अमेरिका, खूबसूरत तिब्बत को हमेशा की तरह एक शक्तिशाली ताकत बने रहने में समर्थन देगा।

हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी अधिकारी अक्सर 88 वर्षीय दलाई लामा से मिलते रहे हैं लेकिन इस बार की मुलाकात इस मायने में खास थी कि अमेरिकी संसद ने तिब्बत को लेकर अहम विधेयक पारित कर दिया है और इसके जरिये अमेरिका के मन में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी भनक शायद दलाई लामा को लग गयी है। इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की दलाई लामा से मुलाकात के दौरान बड़ी बात यह रही कि एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने जब तिब्बत के लिए अमेरिका के समर्थन के बारे में बताया तो दलाई लामा को यह मंजूर नहीं था। साथ ही नैन्सी पेलोसी ने दावा किया है कि तिब्बती नेता दलाई लामा ने चीनी सरकार की आलोचना का समर्थन नहीं किया और बल्कि नैन्सी से आग्रह किया कि वह प्रार्थना करें कि चीन को उसके नकारात्मक रवैये से छुटकारा मिले।

हम आपको बता दें कि यह यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका और चीन ने तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल के महीनों में बातचीत बढ़ा दी है। लेकिन यात्रा और विधेयक के विषय पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर टिप्पणी व्यक्त करते हुए एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 14वें दलाई लामा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लगे एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह दलाई लामा के समूह की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह से पहचाने। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि ज़िज़ांग से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका ने चीन के प्रति जो प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं, उनका सम्मान करते हुए दलाई लामा के समूह के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन आधिकारिक तौर पर तिब्बत को ज़िज़ांग कहता है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वह अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किये गए तिब्बत नीति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करें।

दूसरी ओर, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद तिब्बत की निर्वासित सरकार में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता तेनज़िन लेक्शे ने कहा कि तिब्बत की स्थिति को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के लैंस से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि तिब्बती जीवन शैली की याद दिलाने के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिब्बत अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि चीन इस क्षेत्र को अपने में मिला रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया के नेता तिब्बत के लिए खड़े होंगे, विशेष रूप से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए चीनी नेतृत्व पर दबाव डालेंगे। बहरहाल, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वाशिंगटन और नई दिल्ली अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन को खतरा मानते हैं इसलिए इन दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों पर ड्रैगन की नजर बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत के तत्काल बाद जिस तेजी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन दिल्ली आये और भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के विस्तार पर चर्चा की उससे चीन की भौंहें तन गयी हैं। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चीन की बेचैनी और बढ़ा दी है।

आज का इतिहास

1911 जहाज आरएमएस ओलंपिक ने 5 दिनों, 16 घंटे और 42 मिनट की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क में अपनी पहली ट्रान्साटलांटिक यात्रा पूरी की।
1919 एडमिरल लुडविग वॉन रेउटर ने जहाजों को जब्त करने और मित्र देशों की शक्तियों के बीच विभाजित होने से रोकने के लिए जर्मन हाई सीस फ्लीटिन स्काप फ्लो को स्कैटल किया।
1919 विन्निपेग, मैनिटोबा, कनाडा में विन्निपेग की सामान्य हड़ताल के दौरान, रॉयल नॉर्थवेस्ट माउंटेड पुलिस के सदस्यों ने घोड़ों पर स्ट्राइकरों की भीड़ में घुसने का आरोप लगाया, उन्हें क्लबों और फायरिंगवैपों से पीटा।
1948 मैनचेस्टर स्माल-स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, जो दुनिया का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम चलाया।
1953 पाकिस्तान के इतिहास में लगातार दो बार चुनी जाने वाली इकलौती प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ। वह किसी भी इस्लामी देश की पहली प्रधानमंत्री भी थीं।
1957 एलेन फेयरक्लो ने कनाडा की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
1957 जॉन डायफेनबकर कनाडा के 13 वें प्रधानमंत्री बने।
1963 कार्डिनल जियोवानी बैट्टिस्टा मोन्टिनी पोप पॉल षष्ठम चुने गए।
1964 तीन नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को कुआलक्स क्लान के सदस्यों द्वारा फिलाडेल्फिया, मिसिसिपी, अमेरिका के पास भेजा गया था।
1975 वेस्टइंडीज टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया था।
1977 मुस्तफा बुलेंट एसविट ने तुर्की में सरकार का गठन किया।
1981 दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने दक्षिण अफ्रीकी युवा क्रांतिकारी परिषद के आठ नेताओं को गिरफ्तार किया।
2004 स्पेसशिप वन ने पहली निजी तौर पर वित्तपोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया।
2004 स्पेस शिप वन ने पहली निजी तौर पर वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया।
2005 विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 21 जून, को हाइड्रोग्राफी के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया था।
2006 प्लूटो के नए खोजे गए चंद्रमाओं को आधिकारिक तौर पर निक्स और हाइड्रा नाम दिया गया था। बौने ग्रह प्लूटो में पांच ज्ञात चंद्रमा हैं। प्लूटो से दूरी के क्रम में वे चारोन, स्टाइलक्स, निक्स, केर्बरोस और हाइड्रा हैं।

ताइवान की स्वतंत्रता भारत के हित में है

डॉ. नवीन कुमार मिश्र

चुनाव परिणामों के बाद विश्व भर से आ रहे बधाई संदेशों के बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते और नरेंद्र मोदी के बीच इंटरनेट पर संदेशों के आदान-प्रदान पर चीन ने विरोध जताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। ताइवान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और भारत वन चाइना नीति का पालन करता है। परंतु भारत को चीन के दबाव में आए बिना ताइवान की स्वायत्तता का समर्थन करना चाहिए।

सिंगापुर में दो जून को शांगरी-ला वार्ता सम्मेलन में चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने अपने उग्र भाषण में कहा कि चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में देखता है और एकीकरण प्राप्त करने के लिए सेना ताइवान की आजादी को बलपूर्वक रोकने के लिए तैयार है और जो कोई भी ताइवान को चीन से अलग करने की हिम्मत करेगा, उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाएगा और उसे खुद ही विनाश का सामना करना पड़ेगा'। ताइवान को लेकर बीजिंग की सैन्य और आर्थिक धमकी को लेकर वैश्विक चिंताए बढ़ गई है। ताइवान की राजनीति के इतिहास में सन 1949 से 1987 तक इस द्वीप पर चीनी नेशनलिस्ट पार्टी (केएमटी) का शासन था। यह अब प्रमुख विपक्षी दल है, और ताइवानी प्रणाली के डिज़ाइन के कारण विधायिका में सबसे बड़ी पार्टी है और लोकलुभावन ताइवान पीपुल्स पार्टी के साथ अनौपचारिक बहुमत रखती है। केएमटी के नेता चीन के समर्थक है तथा एकीकरण पक्षधर हैं, जबकि इसके विपरीत एक विशिष्ट विचारधारा रखने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) तीसरी बार सत्ता में आई और नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने 20 मई को अपने उद्घाटन भाषण में ताइवान को लोकतांत्रिक शासन का प्रतीक बताते हुए एक संप्रभु व स्वतंत्र राष्ट्र बताया तथा कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों पक्ष एक दूसरे के अधीन कभी नहीं थे। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) को रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान का औपचारिक नाम) के अस्तित्व को मान्यता देने और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया था। चीन पहले से ही लाई चिंग-ते को अलगाववादी नेता मानता है तथा इस वक्तव्य को वन-चाइना नीति के विरुद्ध मानकर चीन की पीएलए की पूर्वी थियेटर कमांड ने ताइवान और उसके बाहरी द्वीपों के परिक्षेत्र की घेराबंदी कर 23 से 24 मई तक 'संयुक्त स्वार्ड- 2024ए'का अभ्यास किया, जिसे 'ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों लिए एक कड़ी सजा' कहा, जो ताइवान द्वीप पर 'सत्ता को खत्म करने' की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें चीन ने एक नक्शा सार्वजनिक किया जिसमें ताइवान के चारों ओर नौ अभ्यास क्षेत्रों जिसमें ताइवान जलडमरूमध्य, ताइवान द्वीप के उत्तर, दक्षिण व पूर्व के अलावा किनमेन, मात्सु, वुकिउ और डोंगयिन द्वीपों के क्षेत्र शामिल थे। इसके साथ ही पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के चीनी तटरक्षक बलों (सीसीजी) ने 23 मई को अपनी संयुक्त गश्त को त्वरित और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सामरिक व सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण वुकिउ और डोंगयिन द्वीपों के प्रतिबंधित जल-क्षेत्रों में अभ्यास किया। यह अभ्यास पीएलए को युद्ध की परिस्थिति में ताइवान के दक्षिण स्थित काऊशुंग पोर्ट की एक प्रभावी नाकाबंदी करने में सक्षम करने के लिए कारगर सिद्ध होगा, जिससे द्वीप की अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका साबित होगा, क्योंकि यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर है।

चीन इस घेराबंदी के माध्यम से ताइवान व अमेरिका

को कड़ा संदेश देना चाहता था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। पूर्व अप्रैल 2023 में त्साई इंग-वेन के अमेरिका प्रवास के कुछ दिन बाद पीएलए ने पहला 'संयुक्त स्वार्ड' अभ्यास किया था। दो अगस्त 2022 में अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के समय की तुलना में बड़े थे। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को 'ताइवान प्रश्न और नए युग में चीन का पुनर्मिलन' नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया। अक्तूबर 2022 में सीपीसी की नेशनल पार्टी कांग्रेस को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान के एकीकरण को हासिल करने के लिए चीन सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको अब मूर्त रूप देने कि कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के साथ सैन्य व्यवहार को खत्म भी कर दिया।

ताइवान की राजनीतिक स्थिति पर चीन को भय है कि ताइवान एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता भी मिल जाएगी, जिससे मुख्य भूमि के साथ एकीकरण की संभावना नष्ट हो जाएगी। चीन विश्व को संकेत कर रहा है कि उसका राजनीतिक उद्देश्य हांगकांग की तरह ताइवान को 'एक देश, दो सिस्टम' मॉडल पर बातचीत के लिए मजबूर करना है। इसके लिए चीन विगत डेढ़ वर्षों से 'ग्रे जोन' रणनीति काम कर रहा है और ताइवान व अंतरराष्ट्रीय जनमत पर नए तरीके से दबाव देकर ताइवान को बातचीत के जरिये एकीकरण के लिए मजबूर करना चाहता है। इसके लिए ताइवान की जनता के राजनीतिक विचार के साथ मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और फिर व्यवहारिक परिवर्तन प्राप्त करने का उद्देश्य में लगा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन ने ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए आवश्यक सैन्य क्षमताओं के निर्माण के अपने प्रयासों को बंद कर दिया है।

ताइवान का एकीकरण शी जिनपिंग और चीन की सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ताइवान जलडमरूमध्य को आंतरिक जलमार्ग के रूप में दावा करते हुए चीन ने पिछले चार वर्षों में लगभग दैनिक आधार पर ताइवान के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी सेना भेजी है, जिससे ताइवान जलडमरूमध्य की यथास्थिति को बदला जा सके। ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के निकट रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर के लिये एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करती है तथा वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। चीन ताइवान को हड़पने में सफल हो जाता है तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना की आवाजाही भी स्वतंत्र रूप से हो जाएगी, जो हिंद-प्रशांत महासागरीय देशों के लिए सामरिक चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। इस क्षेत्र में ऐसा कोई देश नहीं है, जो चीन के आक्रामकता का मुक़ाबला कर सके। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और आस्ट्रेलिया के साथ इसका प्रभाव भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ताइवान के बाद चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने दावों को लेकर भी आक्रामक हो सकता है। चीन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के माध्यम से भारत की उपेक्षा करते हुए पाक-अधिकृत कश्मीर में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। इसलिए चीन के प्रति भारत को अपने वन चाइना नीति को बदलने की आवश्यकता है।

इसी बीच चीन समर्थक राष्ट्रवादी कुओमिनटांग (केएमटी) और ताइवान पीपुल्स पार्टी (टीपीपी) की बहुमत वाली पार्टी ने नए कानून लागू किए हैं, जो ताइवान की सुरक्षा को कमजोर कर देंगे, रक्षा बजट में कटौती के साथ यह प्रस्ताव न सिर्फ नए राष्ट्रपति लाई की शक्तियों को कमजोर करता है, बल्कि चीन से लड़ने के मनोबल को भी कुंद करता है। अब हालांकि ताइवान की जनता इन प्रस्तावों के पारित होने के बाद विरोध करने सड़कों पर आ गई थी।

चीन के दावे के विपरीत ताइवान के युवा ताइवान के लोकतंत्र की तुलना में चीन का हिस्सा बनने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं और अपनी पहचान ताइवान के निवासी के रूप में देखते हैं। चीन की योजना इस बात को स्पष्ट करती है कि यह ताइवान की राजनीति को अमेरिका, जापान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियोंके बीच एक अविश्वसनीयता पैदा करना चाहता है, तथा ताइवान की स्वतन्त्रता को समाप्त करने के लिए चीन ताइवान में सामाजिक-राजनीतिक अशांति पैदा कर तख्तापलट करने के लिए चीनी समर्थकों का भी उपयोग कर सकता है। चीन की सैन्य मानसिकता व वर्चस्ववादी प्रवृति के कारण ताइवान की स्वायत्तता संकट में दिखाई देती है। इसलिए आवश्यक है कि वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों को उभरने से रोकने के लिए चीन की बढ़ती आक्रामकता को नियंत्रित करने के प्रयास हो, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को संगठित कर चीन के विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया जाए।

जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष चाहता है मतदाता

विश्वनाथ सचदेव

एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजों ने धोखा दे दिया। पिछले दो आम चुनाव के विपरीत इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी की वह आशा कर रहा था। ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसकी उम्मीदें पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकतीं, पर निश्चित रूप से उसे ऐसे नतीजों का अनुमान तो नहीं होगा। चार सौ पार के नारों को गुंजाते भाजपा नेतृत्व को शायद ही अहसास था कि नतीजे ऐसे आएंगे। अब भाजपा वाले यह कह रहे हैं कि चार सौ पार वाला नारा तो एक चुनावी शगूफा था, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और माहौल

बनाने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। यह एक राजनीतिक सच्चाई हो सकती है, पर एक सच्चाई यह भी है कि भाजपा के नेतृत्व को इस बात का आकलन करना ही होगा कि उसकी आशाएं पूरी क्यों नहीं हुई? इस और ऐसे प्रश्नों के तत्काल उत्तर देना शायद जल्दबाजी होगी, पर यह तय है कि देश के मतदाता ने भाजपा की उन नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है जिनके सहारे भाजपा अति विश्वास से ग्रस्त लगने लगी थी। ऐसा नहीं है कि भाजपा को कुछ उल्टा होने की आशंका नहीं थी। ऐसा न होता तो वह हर संभव दिशा से समर्थन जुटाने की कोशिश न करती। जिस तरह इस चुनाव से पूर्व भाजपा ने छोटे-छोटे दलों के साथ समझौते किए और भाजपा नेतृत्व की कटु आलोचना करने वालों को भी अपने पाले में लिया, वह यही बताता है कि भाजपा एनडीए का आधार और आकार बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना चाहती थी। यहां यह स्वीकारना होगा कि मोदी ने भाजपा के प्रचार का सारा बोझ अपने कंधे पर ले रखा था। चुनाव परिणाम का एक चेहरा यह भी है कि मतदाता संविधान और जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है- तानाशाही प्रवृत्तियों से बचना चाहता है वह। यह बात भाजपा के नेतृत्व को समझनी होगी साथ ही यह बात भी रेखांकित हुई है कि मतदाता को हल्के में नहीं लिया जा सकता और न ही यह मानकर चला जा सकता है कि वह राजनेताओं की मुट्ठी में है। एक और बात जो समझने लायक है, वह यह कि मतदाता ऐसी सरकार के पक्ष में है जो अपनी ताकत के गुमान में न रहे और साथ ही वह एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष भी चाहता है।

इस तरह स्पीकर बने थे बालयोगी

उमेश चतुर्वेदी

मार्च 1998 के दूसरे हफ्ते की कोई तारीख..नौ मार्च को चुनाव के नतीजे आ चुके थे..इंद्रकुमार गुजराल सरकार के इस्तीफे के बाद हुए चुनाव की मतगणना 9 और दस मार्च को हो चुकी थी.. तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 265 सीटों के साथ सबसे बड़ा समूह बनकर उभर चुका था, फिर भी वह बहुमत के जादुई आंकड़े से सात सीटें दूर था। चुनाव मैदान में बाजी मार चुके सांसदों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया था..इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बार-बार हिंदी और अंग्रेजी में एक उद्घोषणा हो रही थी..एक नवनिर्वाचित सांसद के लिए बार-बार एनाउंसमेंट हो रहा था. वे खास जगह पर पहुंचें और वहां मौजूद व्यक्ति से संपर्क करें।

जिनके लिए चर्चा हो रही थी, उनके कानों में आवाज पड़ी तो तकरीबन भागते हुए पहुंचे...दरअसल नवनिवार्चित सांसदों को ठहराने का इंतजाम लोकसभा का सचिवालय देखता है। जिनके घर नहीं होते या जो पहली बार चुने जाते हैं, उनके ठहरने का इंतजाम सचिवालय ही करता है। उन्हें हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से रिसीव करके वहां ले जाया जाता है। वह नवेले सांसद सोच रहे थे कि शायद सचिवालय वाले ही उन्हें खोज रहे हैं। यही सोचते हुए वह नवेले सांसद बताई हुई जगह पर पहुंचे..लेकिन वहां का माहौल उनकी सोच से कुछ अलग ही था..उनके सामने लोकसभा स्पीकर के नामांकन के तीन- चार सेट रखे हुए थे। काउंटर पर मौजूद लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जल्दी-जल्दी उनसे उन नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कराया और फिर कार में बैठाकर उन्हें ले उड़े। वह सांसद थे, आंध्र प्रदेश की अमलापुरम् सीट से चुने गए गंति मोहन चंद्र बालयोगी, जिन्हें बाद में इतिहास जीएमसी बालयोगी नाम से याद करता है..

बहुमत के आंकड़े से दूर रह गए एनडीए को तेलुगू

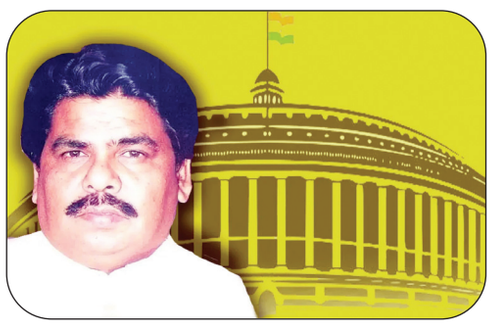

देशम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया था.. दरअसल बहुमत ना मिलने के बाद बीजेपी और एनडीए ने बातचीत के रास्ते खोल रखे थे..एनडीए के संयोजक जार्ज फर्नांडिस का तेलुगू देशम के प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू अच्छे रिश्ते थे..बात बन गई और बारह सांसदों वाली नायडू की अगुआई वाली तेलुगू देशम पार्टी यानी टीडीपी ने वाजपेयी की अगुआई वाली भावी सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया...

टीडीपी ने बदले में मंत्रीपद के साथ ही अपने लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांगा। जयललिता तब एनडीए में शामिल थीं, लेकिन उन्होंने समर्थन पत्र देने में इतनी देर लगाई थी कि उन्हें लेकर बीजेपी सशंकित हो गई थी..इसलिए समर्थन के बदले नायडू की शर्तों को उसने स्वीकार करने के लिए तकरीबन मजबूर होना पड़ा..

तब लोकसभा में टीडीपी के नेता होते थे के येरन नायडू। नायडू वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने बालयोगी को स्पीकर बनाने का फैसला ले लिया। लेकिन इसकी जानकारी बालयोगी को नहीं मिल पाई। तब इतने फोन नहीं होते थे। शायद वे दिल्ली के रास्ते में थे, इसलिए उन तक सूचना पहुंच नहीं पाई। लोकसभा का अध्यक्ष के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, इसमें देर ना हो, इसीलिए बालयोगी का हवाई अड्डे पर बेसब्री से इंतजार हो रहा था। बालयोगी के लिए नामांकन पत्र के कई सेट तैयार रखे गए थे। हवाई अड्डे पर ही उन पर बालयोगी के हस्ताक्षर कराकर एक दल सीधे उन्हें लेकर संसद पहुंचा और उनका नामांकन दाखिल कराया गया। इसके बाद उन्हें करोलबाग के उस खास दर्जी के पास ले जाया गया, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के लिए खासतौर पर सूट तैयार करता था..

बालयोगी ऐसे स्पीकर रहे, जिन्हें नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद पता चला कि वे देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रमुख बनने जा रहे हैं। उन्हें इसके पहले तक इसकी भनक तक नहीं लगी थी।

बालयोगी हालांकि लोकसभा के लिए पहली 1991 में चुने जा चुके थे, लेकिन 1996 में वे हार गए । इसके बाद 1998 में वे दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। पेशे से वकील बालयोगी ने स्पीकर रहते एक गलती की। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के मतदान पर उड़ीसा से कांग्रेसी सांसद गिरिधर गोमांग के मतदान पर फैसला खुद नहीं लिया, बल्कि उनकी अंतरात्मा पर फैसला छोड़ दिया। दरअसल गोमांग कुछ महीने पहले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, यह बात और है कि उन्होंने तब तक लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। गोमांग के मतदान में हिस्सा लेने पर बीजेपी सांसदों, खासकर भदोही के तत्कालीन सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सवाल उठाया था। वह सरकार महज एक वोट से गिर गई थी। कहा जाता है कि अगर बालयोगी ने गोमांग को मतदान से रोक दिया होता तो देश सैकड़ों करोड़ के चुनावी खर्च से बच जाता.. क्योंकि वाजपेयी सरकार बच जाती। संसदीय व्यवस्था के मुताबिक अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो स्पीकर अपना मत किसी पक्ष को दे सकता है। अगर गोमांग को वोट नहीं देने दिया गया होता तो वाजपेयी सरकार के पक्ष और विपक्ष में बराबर-बराबर मत पड़ते, जिसके बाद बालयोगी सरकार के समर्थन में निर्णायक मत दे देते।

क्या यह सिर्फ परिवार का झगड़ा है?

शिव शरण शुक्ला

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या गड़बड़ हुई है? वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन शायद संघ को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व ने नुकसान पहुंचाया है और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाजपा के कई उम्मीदवारों के बारे में चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके कारण वे हार गए, खासकर उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा, कहा गया है कि मोदी ने पिछले सात-आठ साल से संघ के नेताओं से सलाह लेना भी बंद कर दिया है।

मोदी की विराट शख्सियत ने संघ नेताओं के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वे कोई मुद्दा उनके सामने उठाएं। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा में भाजपा के बहुमत हासिल नहीं करने पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि एक सच्चे सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तीखे चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि संघ के भीतर के कई लोगों ने संकेत देने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणियां केवल मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर ही नहीं थीं।

आम तौर पर संघ रोजमर्रा के राजनीतिक मामलों से दूर दिखना चाहता है और वह 2025 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर अपना जनाधार बढ़ाने में व्यस्त है। कुछ संघ कार्यकर्ता राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय संगठन सचिव या संयुक्त संगठन सचिव के रूप में भाजपा के लिए काम करते हैं।

ये कार्यकर्ता पूर्णकालिक होते हैं और उन्हें 'प्रचारक' कहा जाता है। मोदी स्वयं संघ के प्रचारक थे और भाजपा संगठन में सचिव के पद पर थे। भाजपा और संघ के बीच प्रकटत: न तो हितों का टकराव रहा है और न ही सत्ता संघर्ष रहा है, क्योंकि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। बताया जाता है कि संघ नेतृत्व?समझता है कि राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं और भाजपा उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। संघ न तो शासन-प्रशासन और न ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में दखल देने की बात कहता है। केंद्रीय भाव यह है कि वह वैचारिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और आगे भी निभाता

रहेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संघ ने चुप्पी साधे रखी, जबकि ऐसी खबरें भी आईं कि प्रचारक मतदाताओं को एकजुट करने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि भाजपा के बहुमत से चूक जाने के तुरंत बाद आलोचनात्मक स्वर उभरे। भागवत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि क्या संघ ने वास्तव में भाजपा से दूरी बना ली है और चुनाव के दौरान दिल से उसका समर्थन नहीं किया? नतीजों के बाद अपनी पहली टिप्पणी में संघ प्रमुख ने प्राथमिकता के आधार पर मणिपुर संघर्ष खत्म करने और?सरकार तथा विपक्ष के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल दिया था।

आलोचनाओं का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम ने एक अहंकारी पार्टी को लोकसभा में बहुमत पाने से रोक दिया, जो रामभक्त होने का दावा करती थी। फिर एक संघ विचारक रतन शारदा ने संघ के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' में लिखा कि चुनावी नतीजे अति आत्मविश्वासी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व ने चुनाव में सहयोग के लिए संघ के स्वयंसेवकों से संपर्क नहीं किया। संघ के कई नेता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाराज थे, जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि इससे संघ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है।

देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के विपरीत मोदी को पिछले दस वर्षों में संघ से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। उन्होंने संघ और भाजपा के लक्ष्यों को पूरा किया, जिनमें अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। वाजपेयी के उदारवादी रवैये पर केएन गोविंदाचार्य ने टिप्पणी करते हुए उन्हें संघ का मुखौटा कहा था, (हालांकि वह लगातार इस बयान से इन्कार करते रहे)। जाहिर है, वाजपेयी ने उस टिप्पणी के लिए गोविंदाचार्य को कभी माफ नहीं किया और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया। और फिर, गोविंदाचार्य को इस तरह निर्वासित कर दिया कि वे कभी वापस नहीं आए।

लेकिन मोदी संघ का मुखौटा नहीं हैं। वास्तव में वे संघ की विचारधारा के सबसे अच्छे उत्पादों में से एक हैं। साथ ही, मोदी एक ऐसे नेता हैं, जो 2024 के नतीजों को भूलने वाले नहीं हैं। वे विस्तार से पता लगाएंगे कि नतीजे भाजपा के लिए अच्छे क्यों नहीं रहे। इसलिए गहनता से देखें, तो मोदी और संघ के बीच कोई मूलभूत द्वैध नहीं है।

1980 के दशक में संघ ने मोदी को भाजपा को सौंपा था और वह प्रधानमंत्री बने। हां, यह जरूर है कि भाजपा के साथ मोदी की छवि 'लार्जर देन लाइफ' है। ऐसे में, भले ही भाजपा लोकसभा में बहुमत पाने से चूक गई हो, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ और मतदाताओं पर उनके प्रभाव को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। दरअसल, जब भी भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, तो बाहर-भीतर के आलोचक संघ-भाजपा के बीच सत्ता-संघर्ष की काल्पनिक कहानी गढ़ने लगते हैं। संघ अपने 36 संगठनों के माध्यम से 60,000 दैनिक शाखाएं और दो लाख से ज्यादा कल्याणकारी परियोजनाएं चलाने में व्यस्त है। वह 2025 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर आधार मज़बूत करने में जुटा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ गई है और इसमें नेताओं की एक बड़ी जमात है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मोदी जैसे मजबूत नेता के नेतृत्व में पार्टी खुद को संभालने में सक्षम है और आने वाले दिनों में पार्टी को अपनी दिशा खुद तय करनी है। चुनाव नतीजों के कारण अगर कुछ सुधार की जरूरत पड़ी, तो वह भाजपा खुद करेगी। मोदी इतने सख्त हैं कि खुद के साथ-साथ विफलताओं के लिए जिम्मेदार हर तत्व को कसौटी पर कसेंगे। अंतत: जो लोग संघ-भाजपा में सत्ता संघर्ष की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा होगी।

नई सरकार के सामने रोजगार की चुनौती

डॉ. जयंती लाल भण्डारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई एनडीए गठबंधन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नौकरियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की है। निस्संदेह नई गठबंधन सरकार को बेरोजगारी संबंधी चिंताजनक नए आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा। हाल ही में पिछले दस वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में बहुत कम हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्त

वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) में बढ़कर 6 ।7 प्रतिशत हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6 ।5 प्रतिशत थी। शहरी बेरोजगारी पिछली चार तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 15 साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही के 6 ।8 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16 ।5 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है। अब नई सरकार के द्वारा देश में असंगठित सेक्टर, लघु एवं मध्यम उद्योगों और गिग वर्कर्स की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 10 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई स्किल्स से नई पीढ़ी को सुसज्जित करके उनके लिए रोजगार के मौके बढ़ाए हैं। अब तीसरे कार्यकाल में देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) स्थापनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ा जाना होगा। उच्च कौशल, कम लागत, प्रतिभा और मूल्य निर्माण जैसी भारत की विशेषताएं दुनिया में अधिक प्रचारित-प्रसारित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में और ज्यादा जीसीसी स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के द्वारा उनके विकास के एजेंडे में शामिल अधिक रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। हम उम्मीद करें कि नई सरकार नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर पूर्णरूपेण ध्यान देते हुए लघु-मध्यम उद्योग और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की जरूरतों पर ध्यान देगी। हम उम्मीद करें कि मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री डॉ। मनसुख मंडाविया और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी 142 करोड़ से अधिक आबादी के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी को नए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल से सुसज्जित करके उनके चेहरों पर रोजगार की मुस्कुराहट देने के साथ देश की आर्थिक तस्वीर संवारने की संभावनाओं को साकार करने के लिए नई कारगर रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे।

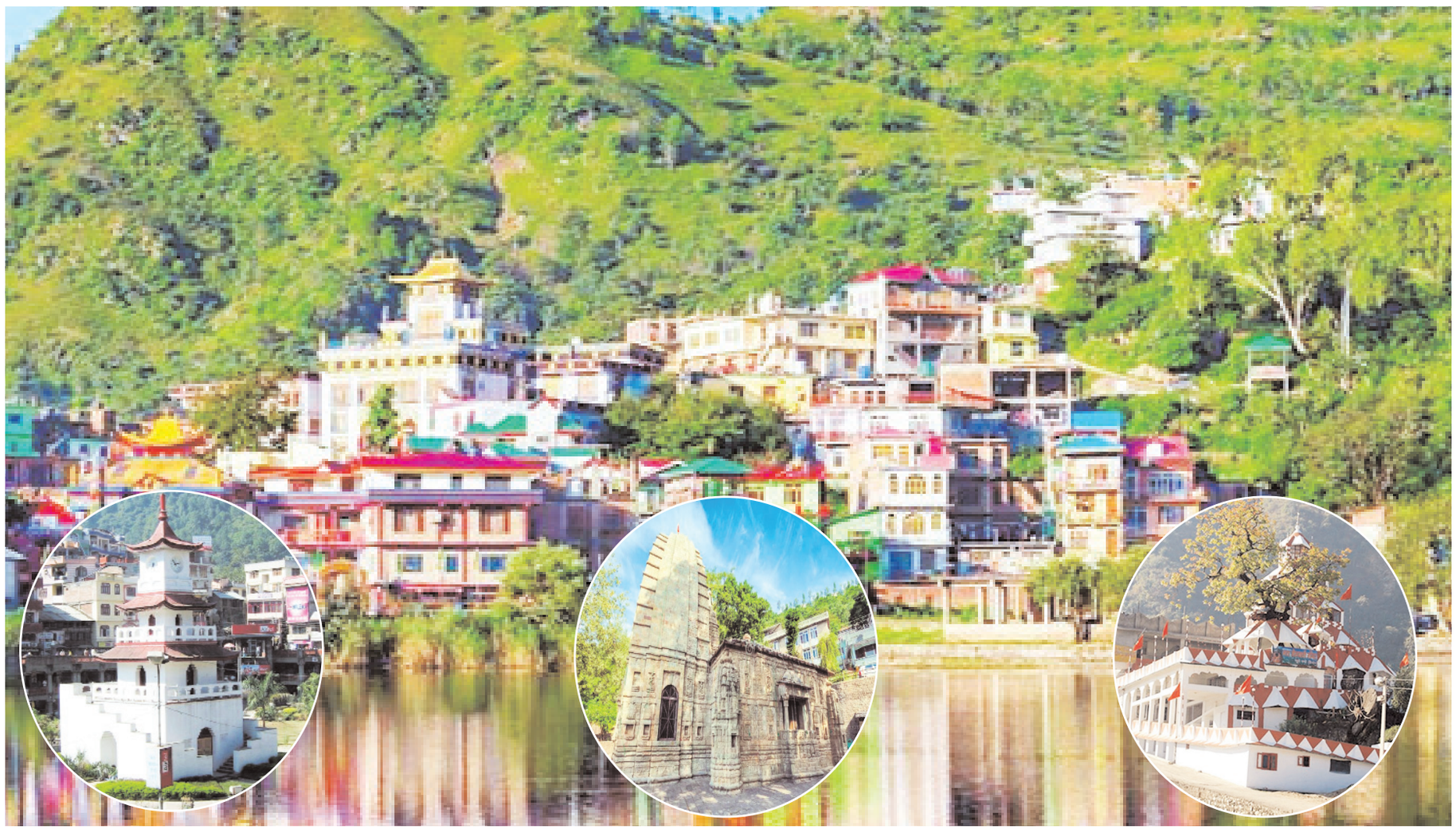

‘हिल्स की वाराणसी’ में हैं 81 मंदिर, खूबसूरत शहर मंडी के बारे ये सब नहीं जानते होंगे आप

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत को जीत मिलने के बाद मंडी शहर चर्चा में बना हुआ है। लोग इस शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हैं। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि मंडी को हिमाचल की काशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अकेले इस छोटे से शहर में 81 हिंदू मंदिर हैं जहां 200 से अधिक देवी देवताओं की उपस्थिति रहती है। चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में दिलचस्प बातें। मंडी जिसका पूर्वनाम मांडव नगर था और तिब्बती नाम ज़होर है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है और ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ हिमाचल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक केन्द्र भी है।मंडी ज़िला जनसंख्या में शिमला के बाद यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखता है और यहां आयोजित नवरात्रि मेला काफी प्रसिद्ध है। इस शहर को वाराणसी ऑफ हिल्स या छोटी काशी या हिमाचल की काशी के रूप में जाना जाता है। बनारस (काशी) में केवल 80 मंदिर है जबकि मंडी में 81 है। मंडी नगर की स्थापना अजबर सेन द्वारा सन् 1527 में हुई। मंडी रियासत सन् 1948 तक अस्तित्व में रही। बाद में मुख्य शहर पुरानी मंडी से नई मंडी में स्थानांतरित किया गया। शहर में कई पुराने महल और वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण के अवशेष हैं। व्यास नदी के किनारे बसा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर मंडी लंबे समय से व्यवसायिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। यह नगर अपने 81 ओल्ड स्टोन मंदिरों और उनमें की गई शानदार नक्कासियों के लिए के प्रसिद्ध है। मंदिरों की बहुलता के कारण ही इसे पहाड़ों के वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। मंडी नाम संस्कृत शब्द मंडोइका से बना है जिसका अर्थ होता है खुला क्षेत्र। मंदिर से नदी और आसपास के क्षेत्रों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। यहां भगवान शिव को तीनों लोकों के भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति पंचानन है जो उनके पांच रूपों को दिखाती है।

पहाड़, झरने, बादल, बारिश का एक साथ लेना है आनंद तो जरुर करें दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सैर

प्रतिष्ठित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) ने हिमालयी शहर और घूम के बीच ‘विशेष जॉयराइड टॉय ट्रेन% शुरू करने के तुरंत बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करते हुए इसे प्रभावित किया है। दो फुट चौड़े ट्रैक पर डीएचआर ब्रिटिश काल वाला एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। विक्टोरियन युग, जिसे यूनेस्को की विरासत का दर्जा प्राप्त है, पहाड़ों की इस रानी की यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए छह जून से डीजल स्पेशल जॉयराइड टॉय ट्रेन सेवाओं का संचालन कर रहा है। दार्जिलिंग और घूम के बीच यह सेवा 30 जून तक जारी रहेगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने इसकी पुष्टि की है। ट्रेन नंबर 02550 (दार्जिलिंग-घूम- दार्जिलिंग) जॉयराइड) दार्जिलिंग से 15ः30 बजे प्रस्थान करेगी और 16ः15 बजे घूम पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन घूम से 16ः35 बजे रवाना होगी और 17ः05 बजे दार्जिलिंग पहुंचेगी। इस ट्रेन में तीन प्रथम श्रेणी चेयरकार कोच शामिल होंगे। दो कोच में 30 सीटें और एक कोच में 29 सीटें होंगी। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई 78 किलोमीटर (48 मील) है। इसकी उन्नयन (ऊंचाई) स्तर न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग 100 मीटर (328 फीट) से लेकर दार्जिलिंग में 2,200 मीटर (7,218 फुट) तक है। स रेलवे को यूनेस्को द्वारा नीलगिरि पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे के साथ भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस रेलवे का मुख्यालय कुर्सियांग शहर में है। इस टॉय ट्रेन सवारी करके आप पहाड़, झरने, बादल, बारिश, ठंड आदि का मजा एक साथ ले सकते हैं। यदि आपने दार्जिलिंग घूमने का टूर बनाया है तो आप टॉय ट्रेन का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलना। यह आपको हर पल एक नए सुखद अनुभव को महसूस कराएगी। यह ट्रेन दार्जिलिंग से पहले विभिन्न बस्ती, मोहल्ले और बाजारों में होकर गुजरती है।

काठमांडू में पार्टनर के साथ इन जगहों को करें एक्सप्लोर

अगर आप भी कम बजट में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो काठमांडू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह नेपाल के खूबसूरत शहरों की लिस्ट में शामिल है। काठमांडू घूमना अन्य विदेशी लोकेशन के मुकाबले काफी सस्ता है। नेपाल में काठमांडू एक ऐसी जगह है, जहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ लगी रहती है। यहां की फेमस जगहों पर घूमने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। बता दें कि यह जगह इतनी ज्यादा सुंदर है कि आपका यहां पर घंटों रुकने का मन करेगा। काठमांडू में प्रकृति के आकर्षक और खूबसूरत दृश्यों के साथ जंगल के बीच ट्रेकिंग और सुंदर-शांत संग्रहालयों को देखना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको काठमांडू की ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

गार्डन ऑफ ड्रीम्स

गार्डन ऑफ ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर आपको लगेगा कि आप सपनों के बगीचे में पहुंच गए हैं। क्योंकि यहां की खूबसूरती आपका मन मोह लोगी। यह काठमांडू का फेमस पर्यटन स्थल है। अगर आप घूमने के बाद थक गए हैं, तो आपको गार्डन ऑफ ड्रीम्स जरूर जाना चाहिए। यहां की ताजगी आपको तनाव से राहत देने का काम करेगी। बता दें कि इस गार्डन को 1920 के दशक में बनाया गया था। आप जैसे ही इस उद्यान में प्रवेश करेंगे, तो आपको हरी घास, फव्वारे और रंग-बिरंगे फूलों का नजारा देखने को मिलेगा। जो आपके मन को खुश कर देगा। बता दें कि काठमांडू एक व्यस्त शहर है। ऐसे में आप शांति और सुकून की तलाश में यहां आ सकते हैं।

तौदाहा झील

आपको बता दें कि काठमांडू से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तौदाहा झील है। यह शांत और मीठे पानी की झील है। यहां की दलदली भूमि और हरी-भरी पहाड़ियां पर्यटकों को खासी पसंद आती हैं। वहीं अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और फोटोग्राफी आदि का शौक रखते हैं, तो आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी।

पशुपतिनाथ मंदिर

बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। यह मंदिर काठमांडू शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर तक आने के लिए आपको टैक्सी, बस या निजी वाहन लेना पड़ेगा।

स्वयंभू मंदिर

इसके अलावा आप यहां पर स्वयंभू मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह काठमांडू शहर से करीब 2 किमी दूर वेस्ट में स्थित है। इस मंदिर को लोग बंदर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। स्वयंभू मंदिर काठमांडू घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। आप बौद्धनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह नेपाल के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है।

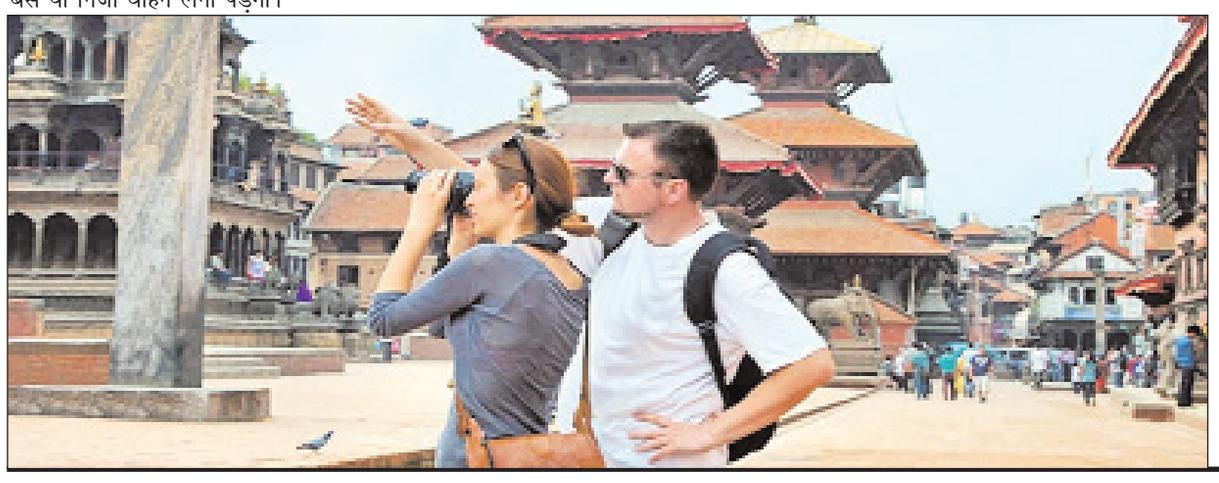

छत्तीसगढ़ की इस रहस्यमयी जगह पर उल्टी दिशा में बहता है पानी

छत्तीसगढ़ भी अब धीर-धीरे पर्यटकों के बीच फेमस हो रहा है। छत्तीसगढ़ की एक जगह पर्यटकों के बीच काफी तेजी से फेमस हुई है। दरअसल, इस जगह की खासियत यह है कि यहां पर उल्टा पानी पानी बहता है। घूमने के शौकीन लोग अक्सर छुट्टियां मिलते ही घूमने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ भी अब धीर-धीरे पर्यटकों के बीच फेमस हो रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में घूमने के लिहाज से कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। बता दें कि इस शहर में एक ऐसी जगह भी है, जो पर्यटकों के बीच काफी तेजी से फेमस हुई है। इस जगह की खासियत यह है कि यहां पर उल्टा पानी पानी बहता है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ की इस जगह पर फ्लो के विपरीत पानी बहता है। इस रहस्यमयी नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक यहां आते हैं। ऐसे में अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ की इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस अद्भुत स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पहाड़ी में मैनपाट बसा है। इसको यहां के शिमला के तौर पर भी जाना जाता है। मैनपाट पर्यटकों के बीच हिल स्टेशन के तौर पर काफी ज्यादा फेमस हो गया है। वहीं इस जगह के फेमस होने मुख्य कारण यहां पर बहने वाला उल्टा पानी पानी है।

मैनपाट समुद्र तल से 3300 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। घने जंगलों के बीच बिसरपानी गांव स्थित है। यह गांव विपरीत बहने वाले पानी के लिए जाना जाता है।

जिस तरफ ढलान होती है, पानी उस तरफ बहने की बजाय उल्टी दिशा में बहता है। इस स्थान पर मौजूद एक आम के पेड़ के पास स्थित भूगर्भ में से यह पानी निकलता है। उल्टे पानी का उद्गम स्थान इस भूगर्भ को ही माना जाता है। शुरूआत में जब पानी निकलता है, तो यह दिशा के साथ ही बहता है। लेकिन 20-25 मीटर आगे तक पहने के बाद पानी 100 मीटर तक ढलान के ऊपर चढ़ता दिखाई देता है। बता दें कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि गांव की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से ऐसा होता है।

हालांकि इस जगह पर पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है। यहां पर लोग दूर-दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ऐसे में आप भी यहां आकर इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जीभी हिल स्टेशन की हसीन वादियों में 3 दिन के लिए बनाएं घूमने का प्लान

घूमना-फिरना आखिर किसे पसंद नहीं होता है। इसलिए जब भी लोगों को ऑफिस या काम से छुट्टी मिलती है, तो घूमने के शौकीन लोग ट्रिप प्लान करके घूमने निकल जाते हैं। जब भी किसी हसीन जगह पर घूमने की बात होती है, तो कई लोग हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल की हसीन वादियों में कई ऐसी खूबसूरत और मनमोहक जगहें मौजूद हैं, जहां पर गर्मी के मौसम में घूमने का अपना ही मजा होता है।

हालांकि घूमने जाने से पहले अगर आपको उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो ट्रिप के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप दिल्ली से 3 जीभी घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको जीभी घूमने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे आप कहां रुक सकते हैं, जीभी कैसे जाएं और यहां पर किन-किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जीभी वॉटरफॉल- जीभी में स्थित जीभी वॉटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह वॉटरफॉल घने जंगलों के बीच में स्थित है और बेहद अद्भुद दृश्य प्रस्तुत करता है। बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में यहां पर वॉटरफॉल के नीचे नहाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं बारिश के दिनों में इस वॉटरफॉल की खूबसूरती चरम पर होती है।

जालोरी दर्रा- जालोरी दर्रा जीभी से करीब 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यह एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहां पर हर रोज हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है।

चन्नी फोर्ट- इसके अलावा आपको जीभी से कुछ दूरी पर स्थित चन्नी फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस फोर्ट को लकड़ी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। बताया जाता है कि यह फोर्ट 1500 साल पुराना है और इस फोर्ट के नीचे एक भूमिगत सुरंग भी है।

ऐसे जाएं जीभी- दिल्ली से जीभी की हसीन वादियों में पहुंचना बहुत आसान है। दिल्ली से जीभी तक आप हवाई मार्ग, ट्रेन, बस या पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं।

हवाई मार्ग-जीभी का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कुल्लू है। आप दिल्ली से पहले कुल्लू हवाई अड्डा जाएं। फिर लोकल टैक्सी या कैब लेकर जीभी की हसीन वादियों में पहुंच सकते हैं। कुल्लू हवाई अड्डे से जीभी की दूरी 60 किमी है।

ट्रेन मार्ग- जीभी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शिमला है। दिल्ली से बस पकड़कर कालका जाएं, फिर कालका से ट्रेन के जरिए शिमला पहुंचे। शिमला रेलवे स्टेशन से लोकल टैक्सी या कैब के जरिए आप जीभी पहुंच सकते हैं। शिमला से जीभी की दूरी 150 किमी है।

सड़क मार्ग- दिल्ली में स्थित कश्मीरी गेट से जीभी के लिए बसें चलती हैं। दिल्ली से शिमला के लिए बस पकड़ लें। फिर शिमला बस स्टैंड से लोकल बस लेकर जीभी की हसीन वादियों में पहुंच सकती हैं। बता दें कि दिल्ली में मजनू का टीला से भी जीभी के लिए बस चलती है।

कहां रुकें- जीभी हिमाचल का एक बेहद खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन है। यहां पर अक्सर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहां पर आपको रुकने के लिए होटल, रिसॉर्ट, विला और कॉटेज आजि आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप सस्ते में स्टे करना चाहते हैं, तो वाइल्डवुड होम, शाइनिंग स्टार होमस्टे, ट्री हब, मैडपैकर्स होटल और जंगल वैली जैसे होटल में रुक सकते हैं। इसके अलावा आप इकोर रिवरसाइड रिसॉर्ट्स, कैवल्य- लक्ज़री रिट्रेट या मंदुक्य विलास में रूम बुक कर सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी से मिला अमेरिका का द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए अमेरिकी संसद के द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका की संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैक्कॉल, पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, ग्रेगोरी मीक्स, मेरिनेटे मिलर मीक्स, निकोल मालियोटाकिस, एमी बेरा और जिम मैकगवर्न शामिल रहे। गौरतलब है कि अमेरिका की संसद ने रिजोल्व तिब्बत एक्ट नामक एक विधेयक पास किया है। यह एक द्विदलीय विधेयक है, मतलब इसे अमेरिकी संसद के दोनों दलों ने मिलकर पेश किया। इस विधेयक के तहत चीन और तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की मांग की गई है।

पटना हाई कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार सरकार के दो कानूनों को अमान्य कर दिया, जिनका उद्देश्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करना था। रिपोर्टों के अनुसार, बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023, और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक माना गया और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है, जो समानता की गारंटी देता है। बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में दो आरक्षण विधेयकों के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी- बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार (शैक्षणिक, संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 कोटा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे आर्थिक और कमजोर वर्ग में 10% जोड़ने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा।

ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। साथ ही साथ आरोप लगाया कि 2022 के गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के 7-सितारा होटल में ठहरने के लिए हवाला पैसे का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल दिल्ली की अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से पेश होते हुए एएसजी राजू ने कहा कि ईडी के पास दस्तावेजी सबूत हैं जो दिखाते हैं कि अपराध की कथित आय का एक हिस्सा 2022 के राज्य चुनावों के दौरान गोवा के ग्रैंड हयात होटल में केजरीवाल के ठहरने की लागत को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह दिल्ली की एक अदालत द्वारा केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है।

मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं शिंदे

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें प्रत्येक महायुति पार्टी से तीन विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा। मानसून सत्र 27 जून को शुरू होगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उससे दो-तीन दिन पहले बहुप्रतीक्षित विस्तार कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि महायुति की नजर मास्टर प्लान के तहत मराठों और ओबीसी को अपने पक्ष में लाने पर है। विशेष रूप से, यह सरकार का आखिरी सत्र होने जा रहा है क्योंकि राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार में तीनों दलों को तवज्जो दी जाएगी। इससे पहले 18 जून को एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में 29 मंत्री हैं। इनमें से शिवसेना और बीजेपी के 10-10 मंत्री हैं जबकि 9 मंत्री अजित पवार की एनसीपी से हैं।

तमिलनाडु में अन्नामलाई ने की राज्यव्यापी विरोध की घोषणा

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने गुरुवार को कल्लाकुरिची जिले में अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों पर राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की। रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक अन्य अस्पताल में भर्ती हैं - जिनमें से पांच की हालत गंभीर है। सूत्रों के अनुसार, कुल 107 लोगों को कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 59 लोगों को सलेम, विल्लुपुरम और पुडुचेरी जैसे अन्य स्थानों के अस्पतालों में भेजा गया है। भाजपा के राज्य प्रमुख ने कहा, कल्लाकुरिची में अवैध शराब पीने के बाद 35 अमूल्य जीवन की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ है। तमिलनाडु भाजपा की ओर से, हम इस भयावह घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दुखों को साझा करने के लिए कल्लाकुरिची का दौरा करेंगे। तमिलनाडु भाजपा शोक संतप्त परिवारों को अपना पूरा समर्थन देती है।

डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर सरकार का विपक्ष से हो सकता है टकराव

नईदिल्ली। भाजपा ने लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों के बीच लगभग सहमति बना ली है। भाजपा के उम्मीदवार पर सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन मिल गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने पर जुट गए हैं। सत्ता पक्ष के संख्या बल और सरकार के साथ उसके सहयोगियों से समन्वय को देखते हुए माना जा रहा है कि स्पीकर के मुद्दे पर आम सहमति बन सकती है। हालांकि, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर टकराव हो सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि अपने संख्या बल को देखते हुए विपक्ष इस बार इससे कम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून से शुरु हो रहे संसद सत्र के पहले विपक्षी दलों के नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। सरकार की सबसे पहली कोशिश विपक्ष के उन दलों के साथ तालमेल बिठाने का है, जिनसे भाजपा के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं, लेकिन ये दल इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं हैं। इनमें बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी शामिल हैं। इसके बाद दूसरे चरण में कांग्रेस सहित दूसरे दलों से सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

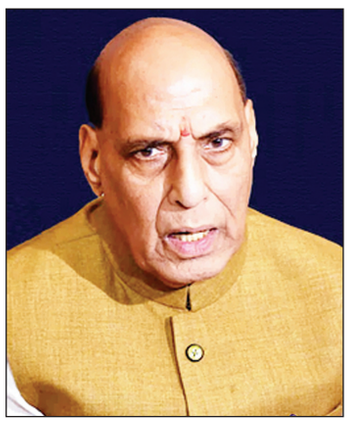

सबसे ज्यादा टकराव डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अमर उजाला को बताया कि पिछले पांच साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। सरकार ने कभी विपक्ष को नेता प्रति पक्ष और डिप्टी स्पीकर का पद देने तक की औपचारिकता नहीं निभाई। जबकि आजादी के समय से लेकर अब तक यह स्थापित परंपरा थी कि सरकार स्पीकर पद अपने पास रखती थी, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन पिछली सरकार ने यह परंपरा भी तोड़ दी थी। लेकिन इस बार हम (विपक्ष) शांत नहीं रहेंगे।

नेता ने कहा कि इस लोकसभा में विपक्ष से कई नेता बहुत अनुभवी हैं और बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में किस नेता का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। नेता के अनुसार, संसद सत्र शुरू होने के पहले एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाकर इस पर गठबंधन के अंदर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।

इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई बैठक में भाजपा के स्पीकर प्रत्याशी को समर्थन देने के मामले पर सबकी सहमति ले ली गई थी। चर्चा है कि भाजपा स्पीकर का पद अपने पास रखने के बाद डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने खेमे के किसी सहयोगी दल को देने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में सबसे पहला टकराव इसी मुद्दे पर देखने को मिल सकता है।

महाराष्ट्र में आरक्षण विवाद पर गरजे शरद पवार

केंद्र दर्शक बनकर नहीं रह सकता, मामलों को हल करें

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र केवल दर्शक नहीं बना रह सकता। उसे मराठा समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा आरक्षण की मांग से संबंधित मामलों को हल करने के लिए पहल करनी चाहिए।

महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर बढ़ते मराठा-ओबीसी संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि इसका एक ही समाधान है कि केंद्र को इसे सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए। इसके लिए कानून तथा राज्य एवं केंद्र की नीतियों में संशोधन की जरूरत है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

इस साल फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया था। हालांकि, समुदाय ओबीसी समूह के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है।

मराठा आरक्षण की मांग के बीच दो ओबीसी कार्यकर्ता जालना जिले में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से यह आश्वासन मांग रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मौजूदा आरक्षण में बदलाव नहीं किया जाएगा। पवार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को नीति में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा, सरकारों, विशेष रूप से केंद्र को दोनों समुदायों की मांगों का समाधान करने में अगुवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन सीमा पार न कर पाए और सामाजिक तनाव उत्पन्न न हो। सरकारें इस मुद्दे पर केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं।

हर परीक्षा में धांधली जारी, छात्रों के साथ हो रहा खिलवाड़

नईदिल्ली। नीट विवाद और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने तंज भरे लहजे में दावा किया कि कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस-यूक्रेन युद्ध रोक दिया। लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने का कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा की मातृ संस्था का कब्जा हो गया है। जब तक इसे उलटा नहीं किया जाएगा, पेपर लीक होते रहेंगे। मोदी जी ने इस कब्जे को आसान बना दिया है। यह एक राष्ट्रविरोधी गतिविधि है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती है। बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक खास संगठन से जुड़े हैं। और इस संगठन और भाजपा ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में घुसकर उसे नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का जो हाल किया, वही अब शिक्षा व्यवस्था का किया है। ऐसा होने का कारण और आप पीड़ित होने का कारण यह है कि एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग यहां दोषी हैं उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह संसद में ह्रश्वश्वञ्ज मुद्दा और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाएंगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं, हां, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि देश में पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इन पेपर लीक का सीधा असर 1.75 करोड़ अभ्यर्थियों पर पड़ा है।

तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे जयशंकर

■ कच्चातीवु द्वीप मुद्दे पर सबकी नजरें

कोलंबो। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को श्रीलंका पहुंचे। यह उनके दूसरे कार्यकाल में पहला दौरा है। इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। कोलंबो पहुंचने पर जयशंकर का स्वागत विदेश राज्य मंत्री थारका बालासुरिया और पूर्वी प्रांत के राज्यपाल सेंथिल थोंडामन ने किया।

जयशंकर ने एक्स पर लिखा, नए कार्यकाल में पहली यात्रा पर कोलंबो पहुंचा हूं। गर्मजोशी से स्वागत के लिए राज्य मंत्री श्रथारकाबालासुरिया और पूर्वी प्रांत के राज्यपाल श्रएसदुथोंडामन का शुक्रिया। नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों का बेसब्री से इंतजार है। उल्लेखनीय है कि इस साल आम चुनावों के समय सरकार द्वारा कच्चातीवु द्वीप मुद्दे को उठाए जाने के बाद जयशंकर की यह पहली यात्रा है।

उन्होंने लिखा, श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर नीतियों का केंद्र है। अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत, भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सागर या क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण और भू-राजनीतिक ढांचा है।

11 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका की यात्रा जयशंकर की एकमात्र द्विपक्षीय यात्रा होगी। जयशंकर पिछले सप्ताह इटली के अपुलिया क्षेत्र में जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री व्यापक मुद्दों पर श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। इसने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद यह विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत की पड़ोसी पहले नीति की पुष्टि करते हुए, यह यात्रा श्रीलंका के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, क्योंकि यह उसका सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और समय की कसौटी पर खरा उतरा मित्र है।

हालांकि, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि क्या मंत्री कच्चातीवु द्वीप मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो देश में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सुलझाया गया था। इसमें कहा गया, यह यात्रा कनेक्टिविटी परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गति प्रदान करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के सात शीर्ष नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से दी मात

एंटीगा। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लगातार जीत के सिलसिले को आठ विकेट से रोक दिया। उन्होंने पहली इनिंग में वेस्टइंडीज को 4 विकेट पर 180 रन पर रोक दिया और फिल साल्ट के नाबाद 87 और जॉनी बेयरस्टो के नाबाद 48 रनों की बदौलत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।

जोस बटलर की अगुआई में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती विकेट लेने की कोशिश की। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने आत्मविश्वास के साथ 101 मीटर का छक्का लगाया, लेकिन ग्रोइन में चोट के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

जोनाथन चार्ल्स और निकोलस पूरन ने क्रीज पर जमने में समय लिया, और वेस्टइंडीज ने बिना किसी नुकसान के 82 रन बना लिए थे। मोईन अली ने चार्ल्स को 34 गेंदों पर 38 रन पर आउट कर दिया, जबकि कसान पॉवेल ने आउट होने से पहले लिविंगस्टोन के एक ओवर में तीन छक्के लगाकर 17 गेंदों पर 36 रन बनाए। पूरन (36) और आंद्रे रसेल भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड की 15 गेंदों पर नाबाद 28 रनों की पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 180/4 का कॉम्पिटिटिव स्कोर बनाया।

वेस्टइंडीज ने अंतिम पांच ओवरों में दो विकेट खोकर केवल 53 रन बनाए, क्योंकि जोफ्रा आर्चर (34 रन पर एक विकेट) और आदिल राशिद (21 रन पर एक विकेट) ने वेस्टइंडीज के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बटलर और साल्ट ने पावरप्ले के दौरान अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि बटलर 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर रोस्टन चेस की गेंद पर आउट हो गए और तीसरे नंबर पर आए मोईन अली 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके सही समय पर लगाए गए बड़े शॉट्स की बदौलत इंग्लैंड नियंत्रण में रहा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 77,479 के ऑल टाइम हाई पर बंद, निफ्टी 51 अंक चढ़ा

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को उछाल देखा गया जिससे सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर पहुंच गए। विदेशी निवेशकों की खरीदारी के बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेटेज वाले शेयरों में लिवाली से बाजार चढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तेजी के साथ 77,554.83 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 77,643.09 अंक के रिकॉर्ड हाई लेवल तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 0.18 प्रतिशत या 141.34 अंक की बढ़त के साथ 77,478.93 अंक के ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्रस्श्व) का निफ्टी भी 0.22 प्रतिशत या 51 अंक की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 23,567 अंक के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील 1.67 परेशात चढ़कर बंद हुआ।

वधावन में 76,200 करोड़ रुपये से बड़ा बंदरगाह बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से हर मौसम में इस्तेमाल के अनुकूल एक विशाल बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस बंदरगाह परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) करेगी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) की एक विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) है। इसमें जेएनपीए और एमएमबी के पास क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बयान के मुताबिक, वधावन में बनने वाला यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। बयान के मुताबिक, बंदरगाह परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है।

सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी

नईदिल्ली। सरकार ने दो अफ्रीकी देशों- मलावी और जिम्बाब्वे को 2,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि निर्यात को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से अनुमति दी गई है। हालांकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अनुरोध पर कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की मंजूरी है। मलावी दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है, जबकि जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र है। अधिसूचना के अनुसार, दोनों देशों को 1,000 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई। भारत ने पहले भी नेपाल, कैमरून, कोट डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स जैसे देशों को ऐसे निर्यात की अनुमति दी है।

ब्लॉक डील के बाद सुजलॉन के शेयरों में लगा अपर सर्किट

नईदिल्ली। रिन्यूबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में आज शानदार उछाल देखने को मिला। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान इसके शेयर 51.34 रुपये पर ट्रेड करने लगे और अपर सर्किट लग गया। कंपनी के शेयरों में यह उछाल ब्लॉक डील के जरिये 179 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री के बाद आई है। एक्सचेंजों पर मौजूद डेटा के मुताबिक, आज कंपनी के 0.3 फीसदी यानी करीब 3.7 करोड़ शेयरों की लेनदेन हुई है। हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन-कौन शामिल रहे। सुजलॉन के शेयर आज 51.34 रुपये पर ओपन हुए, जो आज का हाई लेवल भी है और साथ ही साथ 4 जून 2024 को दर्ज किए गए एक साल के उच्चतम स्तर के काफी करीब है। कंपनी के शेयर 4 जून को इंट्रा डे ट्रेड के दौरान 52 सप्ताह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 52.19 के लेवल पर पहुंच गए थे।

भारत सहित विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे है अपने स्वर्ण भंडार

प्रह्लाद सबनानी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों में रखे भारत के 100 टन सोने को ब्रिटेन से वापिस भारत में ले आया गया है। यह सोना भारत ने ब्रिटेन के बैंक में रिजर्व के तौर पर रखा था और इस पर भारत प्रतिवर्ष कुछ फीस भी ब्रिटेन के बैंक को अदा करता रहा है।

समस्त देशों के केंद्रीय बैंक अपने यहां सोने के भंडार रखते हैं ताकि इस भंडार के विरुद्ध उस देश में मुद्रा जारी की जा सके (भारत में 308 टन सोने के विरुद्ध रुपए के रूप में मुद्रा जारी की गई है, यह सोने के भंडार भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा हैं) और यदि उस देश की अर्थव्यवस्था में कभी परेशानी खड़ी हो एवं उस देश की मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन होने लगे तो इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए उस देश को अपने स्वर्ण भंडार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना पड़ सकता है। इस कारण से विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अपने पास स्वर्ण के भंडार रखते हैं। पूरे विश्व में उपलब्ध स्वर्ण भंडार का 17 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जमा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी 822 टन के स्वर्ण भंडार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसका 50 प्रतिशत से अधिक भाग, अर्थात लगभग 413.8 टन, भारत के बाहर अन्य केंद्रीय बैंकों विशेष रूप से बैंक आफ इंग्लैंड एवं बैंक आफ इंटर्नैशनल सेटल्मेंट के पास रखा गया है। उक्त वर्णित 308 टन के अतिरिक्त 100.3 टन स्वर्ण भंडार भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा है। वर्ष 1947 में भारत के राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही भारत ने अपने स्वर्ण के भंडार बैंक आफ इंग्लैड में रखे हुए हैं। इसके बाद 1990 के दशक में भी भारत ने अपनी आर्थिक परेशानियों के बीच अपने

स्वर्ण भंडार को बैक आफ इंग्लैंड में गिरवी रखकर अमेरिकी डॉलर उधार लिए थे। विभिन्न देशों द्वारा लंदन में स्वर्ण भंडार इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि लंदन पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है और यहां स्वर्ण को सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां के बैकों द्वारा विभिन्न देशों को स्वर्ण भंडार के विरुद्ध अमेरिकी डॉलर एवं ब्रिटिश पाउंड में आसानी से ऋण प्रदान किया जाता है बल्कि यहां पर स्वर्ण भंडार को आसानी से बेचा भी जा सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण के कई खरीदार यहां आसानी से उपलब्ध रहते हैं। कुल मिलाकर इंग्लैंड स्वर्ण का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बाजार हैं। लंदन के बाद न्यूयॉर्क को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण का एक बड़ा बाजार माना जाता है।

भारत को इस स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवर्ष फी के रूप में कुछ राशि बैंक आफ इंग्लैंड को अदा करनी होती थी अत: अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 टन स्वर्ण भंडार को भारत लाने के बाद इस फी की राशि को अदा करने से भी भारत बच जाएगा।

वर्ष 2009 में भारत ने 200 टन का स्वर्ण भंडार अंतरराष्ट्रीय बाजार में 670 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि अदा कर खरीदा था। 15 वर्ष वर्ष बाद पुन: भारत ने अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि करने का निश्चय किया है। स्वर्ण भंडार सहित आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गए हैं और यह भारत के लगभग एक वर्ष के आयात के बराबर की राशि है। अत: अब भारत को अपने स्वर्ण भंडार बेचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसलिए भी भारत ने ब्रिटेन में स्टोर किए गए अपने स्वर्ण भंडार को भारत में वापिस लाने का निर्णय किया है। विश्व में आज विभिन्न देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पास स्वर्ण के भंडार भी बढ़ाते जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में अमेरिका के पास सबसे अधिक 8133 मेट्रिक टन स्वर्ण के भंडार है, इस संदर्भ में जर्मनी, 3352 मेट्रिक टन स्वर्ण भंडार के साथ दूसरे स्थान पर एवं इटली 2451 मेट्रिक टन स्वर्ण भंडार के साथ तीसरे स्थान पर है। फ्रांस (2437 मेट्रिक टन), रूस (2329 मेट्रिक टन), चीन (2245 मेट्रिक टन), स्विजरलैंड (1040 मेट्रिक टन) एवं जापान (846 मेट्रिक टन) के बाद भारत, 812 मेट्रिक टन स्वर्ण भंडार के साथ विश्व में 9वें स्थान पर है।

प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू

किसान सम्मान निधि मिलने और धान खरीदी समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों में उत्साह का माहौल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की बौछारों के साथ खेती-किसानी का काम शुरू हो गया है। हाल ही में केन्द्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने और धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों में नया उत्साह दिख रहा है। किसान गांव में खेतों की जोताई-बुआई आदि के कार्यों में जुट गए हैं। राज्य की कुछ हिस्सों में बोनी का काम भी शुरू हो गया है। चालू खरीफ वर्ष में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों

बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने अपने सरकार के 06 माह पूर्ण होने के बाद कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के किसानों को सुगमता से उनके मांग के अनुरूप किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज भण्डारण करने को कहा है। किसानों के उत्साह उस समय दुगुना हो गया जब केन्द्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 117 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का का निर्णय लिया।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 7.46 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.64 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो मांग का 47 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 9.43 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 11.23 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 6.22 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। जो लक्ष्य का 46 प्रतिशत है। जबकि गत् वर्ष खरीफ 2023 में कुल 13.41 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1232.7 मि.मी. है। 18 जून 2024 की स्थिति में राज्य में औसत वर्षा 27.2 मि.मी. दर्ज की गई है जो इसी अवधि की 10 वर्षों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से औसत वर्षा 68.4 मि.मी. से 41.2 मि.मी. कम है। गतवर्ष इसी अवधि में 3.3 मि. मी. वर्षा दर्ज की गई थी।

पीएससी घोटाला कर युवाओं का भविष्य चौपट करने वाली कांग्रेस किस मुंह से युवाओं की बात कर रही है

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के आंदोलन को फिजूल की सियासी कवायद बताया है। भगत ने कटाक्ष किया कि प्रदेश के कोरोना काल में शराब के गोरखधंधे की कोचियागिरी में लगी जिस कांग्रेस सरकार ने रोजगार को नाम पर प्रतिभासम्पन्न शिक्षित बेरोजगार युवकों को डिलीवरी ब्वॉय तक बनाने का शर्मनाक कृत्य किया हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में पीएससी घोटाला करके युवकों के अधिकारों पर डाका डालने में कोई हिचक जिस भूपेश सरकार को नहीं हुई, आज वह कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को मुद्दा बनाकर अपने बचे-खुचे राजनीतिक वजूद की जगहँसाई करा रही है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि आज हताश-निराश और अपने राजनीतिक वजूद के लिए छटपटाती कांग्रेस नीट पेपर लीक और रोजगार के नाम पर छत्तीसगढ़ को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रही है और यह सच्चाई खुद-ब-खुद गुरुवार को कांग्रेस के एक और फ्लॉप शो से सामने आई है। सवाल यह है कि आखिर युवकों के साथ रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर अपने पूरे शासनकाल में छल-कपट करने वाली कांग्रेस आज फिर युवकों के हक की बात करके युवाओं को बरगला रही है.

योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुचाएंः शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ का पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ क्रियान्वयन हों और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचना चाहिए। वें आज कबीरधाम जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राज्य तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम एवं कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के

कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को खाद, बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो किसानों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के एक भी पात्र किसान योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय सहित स्कूल भवन के बेहतर रख रखाव होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने बीईओं एवं स्कूल समन्वयकों को स्कूलों का निरीक्षण करने और सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा में कहा कि तकनीकी समस्या के कारण छूटे हुए 14 ग्रामों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बोडला विकासखण्ड के 179 ग्राम और पंडरिया विकासखण्ड के 77 ग्राम शामिल है। इस दौरान उन्होंने वनांचल क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।

विष्णु के सुशासन में जनता के साथ विपक्ष भी खुश

भूपेश के साथ कांग्रेसी भी खुश है भाजपा सरकार में धान का पूरा 3100 रु मिल रहा है वो भी एकमुश्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से जनता और किसान बहुत खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट का हवाला देते हुए श्री कश्यप ने कहा कि जनता तो जनता, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने धान की खेती करते हुए बहुत हर्ष के साथ एक पोस्ट किया है जिसमें वह बहुत खुश दिख रहे हैं। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बघेल को भी अब धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी और वह भी चार किश्तों में नहीं मिलेगी बल्कि एकमुश्त मिलेगी। इसी प्रकार धान की खरीदी कांग्रेस की तरह 15 क्विंटल नहीं, बल्कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की जा रही है। यही तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन है जिसमें जनता के साथ-साथ विपक्ष

के कांग्रेस के नेता यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी प्रसन्न हैं। श्री कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल ने बड़े हर्ष के साथ धान की खेती की तैयारियों का जायजा लिया है। ऐसा हो भी क्यों न, आखिरकार उन्हे भी पूरे 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत मिलेगी। अब कांग्रेस की सरकार तो चली गई और विष्णु के सुशासन में सब खुश हैं। कश्यप ने कहा कि बघेल भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ चाहे जितना अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश में अपने राजनीतिक झूठ का रायता फैलाएँ, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार के किसान हित के फैसलों का लाभ बघेल को भी उतना ही मिला है और आगे भी मिलेगा,.

मोदी सरकार ने आते ही किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए

किसान सम्मान निधि और अब एमएसपी में वृद्धि मोदी सरकार के किसान हितैषी होने का बड़ा प्रमाणः संदीप शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने धान समेत कृषि उत्पादों के बढ़े हे नए समर्थन मूल्य की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार का आभार व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। धान के समर्थन मूल्य में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और इससे देश के साथ-साथ प्रदेश के किसानों में भी हर्ष व्याप्त है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि जहाँ तक सवाल है दलहन और तिलहन के दामों का, तो तिलहन के दामों में 983 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है, यह अपने

आपमें एक अकल्पनीय बढ़ोतरी है और यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार किसानों को कैश क्राफ्ट की खेती की तरफ ले जाना चाहती है और इसका परिणाम यह होगा कि देश में दालों और तेल के आयात में कमी आएगी और विदेशी भुगतान संतुलन में भी इसका फायदा मिलेगा। बाजरा, ज्वार और रागी के दाम में जो बढ़ोतरी की गई है उससे मिलेट की खेती करने वाले किसानों में काफी उत्साह है। रागी, ज्वार और बाजरा के जो दाम है, उनमें 2014 की तुलना में लगभग 100त्न की बढ़ोतरी हो चुकी है। दलहन और तिलहन में 2014 की तुलना में 85 से लेकर के 100त्न तक की बढ़ोतरी हुई है जबकि धान की फसलों में यह बढ़ोतरी 2014 की तुलना में वर्तमान कीमत लगभग 72त्न की बढ़ोतरी है।

इन सबको देखकर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मोदी सरकार किसानों के प्रति चिंतनशील है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए के हुए इजाफे के बाद कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार को किसानों का धान अब 3,217 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की दी गई सलाह पर तीखे लहजे में पलटवार करते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस ने धान बोनस के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ पूरे पाँच साल धोखाधड़ी करने के सिवाय कुछ नहीं किया, जिस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सैकड़ों किसानों को कर्जमाफी का पाखण्ड रचकर आत्महत्या के लिए विवश किया, वह कांग्रेस किसानों के नाम पर घड़ियाली आँसू न बहाए।

लेटलतीफी, अचानक रद्द होना भारतीय रेल की पहचान बन गयी हैः कांग्रेस

रायपुर। मोदी सरकार यात्री ट्रेनों को नहीं चला पा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिये चलती है। घंटो लेट लतीफी भारतीय रेल की पहचान बन गयी है। यह मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को बिना किसी ठोस कारण के रद्द किया जाता है वर्तमान में एक बार फिर एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 40 ट्रेने पहले से रद्द है। कुल 50 से अधिक ट्रेनें रद्द है। यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नाईसांफी है। दिल्ली मार्ग की अधिकांश ट्रेने रद्द है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
21 जून 2024
हार्दिक शुभकामनाएं

योग से हमें असीम शांति मिलती है,
हम जीवन की चुनौतियों का सामना
शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं।
- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

योग
तन और मन रहे निरोग

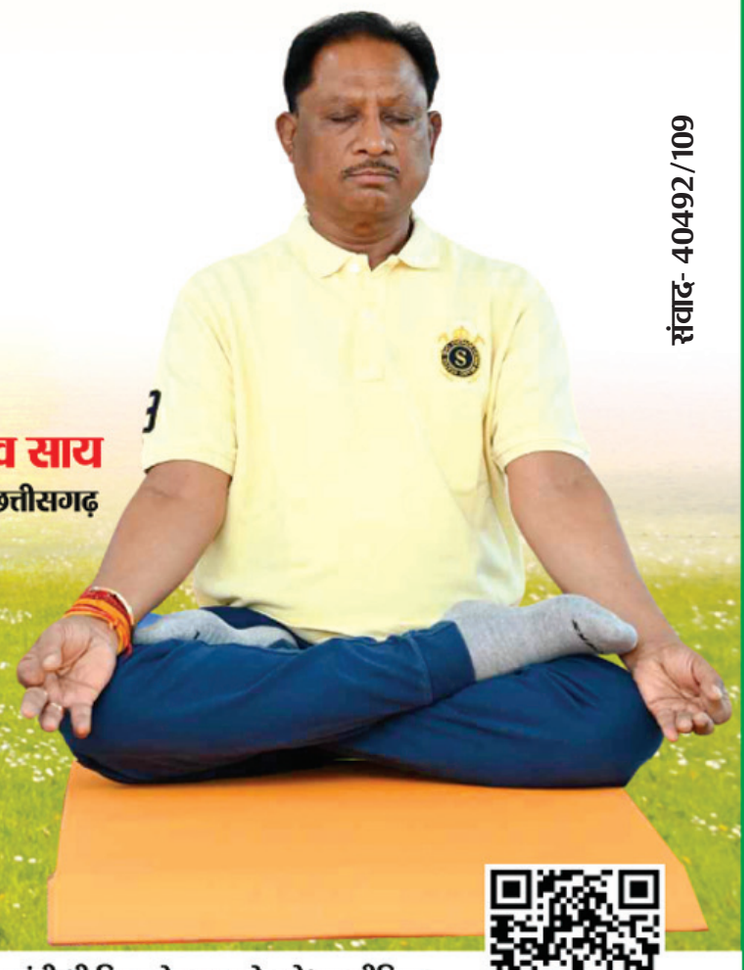

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें ...

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

संवाद- 40492/109

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.